आप से । अगर सरदार साहब को कोई सुविधा हो जाती है, तो आखिर को वह मेरे दोस्त हैं, एक साथ बैठते हैं ।

श्री मधु लिमये : उनकी बात सुनने के बाद मुलतवी रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय : फिर किस दिन चाहते हैं, उस दिन रख लेता हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्यों सरदार साहब ? ठहरिये, एक सेकेण्ड मैं पूछ लूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ही कह दीजिये, उन्होंने कह दिया है ।

Shri Kapur Singh: I have made a submission that as this is of a legal and technical nature, Members should be allowed some time.

Mr. Speaker: How much time, I am asking.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मंगलवार को रख सकते हैं, क्योंकि हम में से कुछ चले जायेंगे ।

Mr. Speaker: After the debate on the no-confidence motion, we will take it up.

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इस बहस हिस्सा लूं तो थोड़ा सी इनायत करें कि मुझे दिन बता दें, क्योंकि मुझे भी इधर-उधर जाना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : बार बार आप ही से पूछ रहा हूं, आप बताइये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर आप रख सकें तो अगले वीक को रख लें, आप सोच लें और मुझे बता दें ।

—

13.20 hrs.

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Dr. K. L. Rao on the 27th July, 1966, namely:—

> "That the Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948, be taken into consideration."

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): I have done, yesterday.

Mr. Speaker: Then there is an amendment by Shri Nambiar, to refer the Bill to a Select Committee.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Yes, Sir. I beg to move:

> "That the Bill be referred to a Select Committee consisting of 12 members namely: Shri Bhagwat Jha Azad, Shri Bibhuti Mishra, Shri N. Dandeker, Shri Hari Vishnu Kamath, Shri Jaganath Rao, Dr. K. L. Rao, Dr. L. M. Singhvi, Shri U. M. Trivedi, Shri R. Umanath, Shri K. K. Warior, Shri Yashpal Singh and Shri Ananda Nambiar, with instructions to report by the last day of the first week of next session." (19)

Mr. Speaker: Both the motions are before the House.

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अमेंडमेंट भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका अमेंडमेंट सर्कुलेशन के लिये है ।

श्री विभूति मिश्र : मैंने बिल में अमेंडमेंट भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय : तब क्या आपने सेलेक्ट कमेटी के लिये अमेंडमेंट भेजा है ?

श्री विभूति मिश्र : जी नहीं, क्लाज के ऊपर है ।

अध्यक्ष महोदय : तब वह तो बाद में आयेगा जब कि क्लाजज लेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : इसके लिये कितना समय दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये 4 घंटे रखे गये हैं जिसमें से 15 मिनट हो चुके हैं । 3 घंटे और 45 मिनट और बाकी रहते हैं ।

श्री बड़े (खारगौन) : अध्यक्ष महोदय, यह बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक जो हाउस के सामने आया है उसके बारे में मझे तीन या चार बातें कहनी हैं । इस बिल में कहा गया है कि पहले जहां पर किसी भी स्कीम को घोषित करने का नियम था उस की जगह पर इसको अमेंड किया जा रहा है कि अगर कोई भी स्कीम 25 लाख रु० की या इससे कम की हो तो उसको पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है । उसको वेस्टफुल और अन-निसेसरी बतलाया गया है । पेज 15 पर लिखा गया है कि :

> "In accordance with the procedure laid down in the Act in respect of sanctioning of these schemes by the State Electricity Board, all schemes are required to be published in the Official Gazette and local newspapers twice; first as draft schemes, and again as sanctioned schemes. This procedure has been found to be wasteful and unnecessary in the case of small schemes. Provision has, therefore, been made in the Bill to provide that schemes costing up to Rs. 25 lakhs need not be published at all."

दि अ इंडिया हुंज डान्ड अ न दि अंन कि इसकी जरूरत नहीं है । इसके बारे में मुझे बड़ी आपत्ति है । एक आपत्ति तो यह है कि 25 लाख रु० की जो स्कीम होगी या उसके नीचे की होगी उसको पब्लिश करने की आवश्यकता सरकार नहीं समझती । उसका कहना है कि यह वेस्टफुल और अननिसेसरी है । मैं समझता हूं कि यदि 1 करोड़ रु० या 25 लाख रु० के ऊपर की स्कीम को पब्लिश करना वेस्टफुल नहीं है तो 25 लाख के नीचे की स्कीम को भी पब्लिश करना वेस्टफुल नहीं है । आज हमारे यहां ब्यूरोक्रैसी का राज्य चल रहा है और बोर्ड में उनकी मनमानी चलती है । वह लोग सोचते हैं कि 25 लाख और उससे ऊपर की स्कीम को तो पब्लिश करना होगा और 24 लाख की स्कीम को पब्लिश करना नहीं होगा । इसलिए वह कम की स्कीम रख देंगे । उसके बाद अगर स्कीम में कुछ कमी पड़ेगी तो 2 या 3 लाख रु० और मांग लेंगे । नतीजा यह होगा कि 24 लाख की स्कीम की जगह वह 27 या 30 लाख की स्कीम हो जायेगी । जिस तरह से चम्बल योजना पहले 9 करोड़ की थी लेकिन होते होते वह 90 करोड़ की हो गई । इसी तरह से हर स्कीम को पहले कम रुपये की बताया जाता है उसके बाद कह दिया जाता है कि इसमें कुछ बातें बाकी रह गई हैं, खर्च बढ़ गया है, मजदूरी बढ़ गई है, मशीनरी की कीमत ज्यादा बढ़ गई है, इस वास्ते यह स्कीम ज्यादा की हो गई । इस लिए जो आप ने बतलाया कि 25 लाख की स्कीम जो होगी उस को पब्लिश करना वेस्टफुल और अननिसेसरी है, यह ठीक नहीं है क्योंकि उसका दाम बढ़ जायेगा । फिर अगर 25 लाख की स्कीम वेस्टफुल और अननिसेसरी है तो फिर 26 लाख की स्कीम वेस्टफुल कैसे नहीं होगी । आज हम देख रहे हैं कि सन् 1948 से जो एलेक्ट्रिसिटी विभाग चल रहा है उस में आज तक अन-निसेसरी खर्च बढ़ता गया है । लेकिन आज एक दम से दिमाग में यह बात आ गई है कि 25 लाख और इस से कम की स्कीम को पब्लिश करना वेस्टफुल और अननिसेसरी है । मैं समझता हूं कि इन स्कीम्स को पब्लिश न करने का कोई कारण नहीं हो सकता है और उन का घोषित करना वेस्टफुल और अन-निसेसरी नहीं है ।

इस में एक और महत्वपूर्ण बात है। इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट के मुताबिक अगर कोई लाइसेंसी कम्पनी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से टेक ओवर करती थी तो उसका जो कर्जा होता था उस के लिये केवल तीन साल का लिमिटेशन था। लेकिन अब इस विधेयक में यह संशोधन लाया जा रहा है कि यदि किसी प्राइवेट कम्पनी से एलक्ट्रिसिटी बोर्ड लेता है या गवर्नमेंट लेती है और उस कम्पनी का किसी दूसरी कम्पनी पर लेना हुआ या किसी प्राइवेट आदमी पर हुआ तो अब उसके लिये 60 साल का लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। मैं कहता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय है। जो हमारे सिविल राइट्स हैं, जिसके लिये सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया है, जिस में कि लिमिटेशन ऐक्ट भी है, उस में यह प्राविजन किया गया है कि किसी प्राइवेट कम्पनी से टेक ओवर करता है एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो उस पर साठ साल का लिमिटेशन लागू होगा। आखिर यह कौन सा जूरिस्प्रूडेंस है कि जिस कर्जे पर तीन साल की मर्यादा थी उसको बोर्ड के द्वारा लेने पर साठ साल किया जा रहा है, जिसके लिये ऐसा मान लिया जायेगा कि यह गवर्नमेंट मान है। यह बात बिल्कुल अन्याय की है।

दूसरी बात रिट्रास्पेक्टिव की है। लेकिन आपने सुझाव दिया है कि रिट्रास्पेक्टिव नहीं होना चाहिये।

इस के बाद इस ऐक्ट में यह था कि कोई भी पार्लियामेंट का मेम्बर वहां से हटने के बाद एक साल तक एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मेम्बर नहीं बन सकता था। लेकिन अब इस चीज को विधेयक में से हटाया जा रहा है। गवर्नमेंट शायद समझती है कि पार्लियामेंट के जो मेम्बर होते हैं वह अक्ल का ठेका लेकर आते हैं, वह होशियार लोग होते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो हम से ज्यादा होशियार हैं। आज जो इस में यह लिखा हुआ था कि जो पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं रहता है वह एक साल तक बोर्ड का मेम्बर नहीं बन सकता उस प्राविजन को इसमें से निकाला जा रहा है। अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर आज है और अगले एलेक्शन में हार जाता है तो उसी साल वह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मेम्बर बन सकता है। मैं इस के मतलब को समझता हूं। कांग्रेस पक्ष के पास कुछ मुहरे रहते हैं। कोआपरेटिव सोसायटीज के डाइरेक्टर्स रहते हैं बैंक के डाइरेक्टर्स रहते हैं उन में जो भी नामिनेट होते हैं वे कांग्रेस पार्टी के होते हैं। अगर उन को शंका हो गई कि कोई जन संघ का मेम्बर आ गया तो उस को निकाल दिया जाता है। मैं ने मध्य प्रदेश में देखा हुआ है कि हमारे यहां के आदमी को बैंक से निकाला गया और कांग्रेस के एक्स एम० एल० ए० जो कि एलेक्शन में हार गये थे उन्हें डाइरेक्टरों के बोर्ड पर रक्खा गया, बिना किसी वजह के। मैं ने कल पत्र लिखा है कि यह हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वह कहते हैं कि उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई रीजन नहीं है कि पार्लियामेंट के मेम्बर को इसके बारे में बतलाया जाये। यह प्राविजन सिर्फ इसलिये रक्खा जा रहा है कि जो उनके मुहरे होते हैं उनको एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर उन को लेना पड़ता है। चूंकि उन मुहरों को एलेक्शन के लिये टिकट नहीं मिलता है इसलिये उनको नाराजगी होती है चूंकि उनको नाराजगी होती है इसलिये उनको सांत्वना देने के लिये इस प्राविजन को इस में से निकाल दिया गया है ताकि जो एम० पी० एलेक्शन में हार जायें या जिन की पार्लियामेंट को जरूरत नहीं है उन को एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर रखा जाये।

इस विधेयक में मैं एक और चीज देखता हूं कि हर एक प्रदेश में अलग अलग बिजली

[श्री बड़े]

के रेट्स हैं। मद्रास में रेट्स सब से कम हैं. हमारे यहां सब से ज्यादा हैं।

13.28 hrs.

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

अगर कभी चम्बल में पानी की कमी हो जाती है तो कारखाने वगैरह बन्द हो जाया करते हैं क्योंकि पावर कट हो जाया करता है कंज्यूमर्स जो होते हैं उन की बिजली भी कम कर दी जाती है। अगर 50 प्रतिशत कट हो गया तो भी हम को मिनिमम पैसा देना पड़ता है। यह तो छोड़िये जब मैं यहां रहता हूं और बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं तब भी मुझको 4 रु० का मिनिमम खर्च देना ही पड़ता है। चार रुपये उसको देने पड़ते हैं जबकि वह दो रुपये की बिजली भी खर्च नहीं करता है। इसका कारण यह है कि आपने रूल बना रखा है कि मिनिमम उसको देना ही पड़ेगा। हजारों बार इसके बारे में शासन को लिखा जा चुका है कि मिनिमम देने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। वह अपने इंजिन के पास रात को अंधेरे में जाता है तो उसको कहीं सांप या बिच्छू न काट खावे या शेर उसको न खा जाये इनसे अपना बचाव करने के लिये उसने अगर अपने कुएं पर एक बिजली का टिमटिमाता हुआ बल्ब लगा लिया तो उसको कहा जाता है कि तुमने इलैक्ट्रिफाई कर लिया है और तुम पूरा चार्ज दो। यह और इस तरह की कई दूसरी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की मनमानियां चलती हैं। अगर उसने एक छोटा सा बल्ब इसके लिये लगा लिया है और इस कारण से उस पर पूरा चार्ज लगा देना और जो कमेंशन उसको मिलता है वह भी न देना उस के साथ अन्याय करना है। यह ठीक नहीं है।

जो पावर पम्प लगाये भी गये हैं बिजली के अभाव में, पावर के अभाव में बेकार पड़ हुए हैं। वैल्ज को इलैक्ट्रिफाई नहीं किया जा रहा है। पम्प वे किसी तरह से ले आते हैं तो पावर का पता नहीं। इधर पावर का पता नहीं है और उधर भगवान ने पिछले साल पानी नहीं बरसाया। इधर पावर का पता नहीं और उधर पानी का पता नहीं। ऐसी अवस्था में एग्रिकल्चर को कैसे तरक्की दी जा सकती है। रेट भी आप कम नहीं करते हैं। ये सब जो चीजें हैं इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

हिन्दुस्तान में पांच लाख से ऊपर गांव हैं। मैं आप से जानना चाहता हूं कि कितने गांव आपने इलैक्ट्रिफाई किये हैं। नब्बे करोड़ रुपया आपने चम्बल पर खर्च किया। इतना खर्च करने के बाद भी आप बतायें मध्य प्रदेश में आप ने कितने गांवों को बिजली दी है। मैं समझता हूं कि 25 हजार या 26 हजार गांव ही इलैक्ट्रिफाई हुए हैं। इतने ही पांच लाख में से मैं समझता हूं इलैक्ट्रिफाई हुए हैं। बाकी बिना बिजली के ही पड़ हुए हैं।

आप ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया है। मैं समझता हूं कि जय किसान का नारा तो आप ने वोट लेने के लिए दिया है और जय जवान का नारा उनको आप ने लड़ने के लिए दिया है। आप बिजली के रेट्स बढ़ाते जाते हैं। किसान को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है शायद यह आपको पता नहीं है। उसको बिजली लेने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं शायद यह मंत्री महोदय को पता नहीं है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मैं अपने गांव में तथा आसपास के गांवों में बिजली लेना चाहता था,

वहां के लोग बिजली लेना चाहते थे, इलैक्ट्रिफाई करना चाहते थे । यह अंदाजा लगाया गया कि बाईस कुएं होने चाहियें । इसके बाद सवाल गारंटी का पैदा हुआ कि वह देनी चाहिये । गारंटी के बाद वह स्कीम जबलपुर गई । फिर यह हुआ कि चारसौ मजदूर जबलपुर जायेंगे । वहां से इंदौर जायेंगे । इंदौर से फिर जबलपुर जायेंगे । ऐसा करते करते एक सीजन निकल गया । दूसरा सीजन आया तो उनको बता दिया गया कि प्लान में आप के गांव के लिए बिजली नहीं है दूसरे गांवों को बिजली दी जायेगी । इस तरह से काश्तकार एक जगह से दूसरी जगह ठोकरें खाता फिरता है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटकता फिरता है, धक्के खाता फिरता है लेकिन उसको बिजली नहीं मिलती है । मैं समझता हूं कि यह जो बिल आया है इसके फलस्वरूप आपने काश्तकार को सस्ती दर पर बिजली दी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी । एग्रिकल्चरिस्ट को आप ने जितनी पावर दी है, जितनी बिजली दी है और जितनी देंगे अगर वह आप ने सस्ते दर पर दी तो जनता आप को धन्यवाद देगी । लेकिन यह जो अमेंडमेंट आप लाये हैं कि पच्चीस लाख वाली का डेक्लेरेशन हो इसका मैं और विरोध करता हूं । मुझे इस में कुछ दाल में काला मालूम पड़ता है, इस में मुझे कुछ गड़बड़ी मालूम पड़ती है । पच्चीस लाख ही आपने क्यों किया है, पचास लाख क्यों नहीं किया, दस लाख या पंद्रह लाख क्यों नहीं किया .

सभापति महोदय आप फिर वही आर्गुमेंट दे रहे हैं ।

श्री बड़े : मैं समाप्त कर रहा हूं । पच्चीस लाख क्यों रखा यह मैं समझ नहीं पाया हूं । आप के मन में कोई स्कीम है, कोई बात है जो आप पच्चीस लाख रख रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और सिवाय दो चार एमेंडमेंट्स के बाकी तमाम एमेंडमेंट्स इनके गलत हैं । मैं समझता हूं कि यह जो इनका कदम है यह आगे ले जाने वाला कदम नहीं है, पीछे ले जाने वाला कदम है ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, इस मौके पर हमारे विद्युत् मिनिस्टर साहब एक इम्पार्टेंट बिजली संभरण एमेंडमेंट बिल लाये हैं । यह सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ ले जाने की दिशा में एक कदम सिद्ध होगा । इसमें इन्होंने कहा है :

> Few amendments are also proposed to tighten the control over the financial operations of private licensees.

मंत्री महोदय ने कहा था कि 214 लाइसेंसीज हैं जिन के अपने एंटरप्राइज (विद्युत्) है । स्वराज्य के बाद हमने देखा है कि आठ सौ के करीब देशी राजाओं को, उनकी रियासतों को आपने खत्म किया और एक नये हिन्दुस्तान का आपने निर्माण किया । उसी तरह से अब रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन (साम्य विद्युतकरण) के सिलसिले में एक नया चैप्टर हमारे डा० राव साहब जोड़ने जा रहे हैं इस बिल के पीछ । छठे शैड्यूल में उन्होंने चाहा है कि 1910 का जो विद्युत् एक्ट है उसको अच्छ संशोधित ढंग से लागू किया जाए । यह कहा गया है :

> The licensee shall so adjust his rates for the sale of electricity whether by enhancing or reducing them that his clear profit in any year of account shall not, as far as possible, exceed the amount of reasonable return:

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है ।

सभापति महोदय : मन्डल साहब आप तशरीफ रखिये । कोरम चैलेंज किया गया है । घंटी बज रही है । कोरम हो गया है माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : मैं यह कह रहा था कि इस विद्युत (संभरण) बिल छटे शैडयूल में मंत्री महोदय ने एक बड़ी अच्छी एमेंडनेंट लाने की कोशिश की है । यह जो 1910 का कानून है यह बहुत पुराना है । बार बार यहां कहा गया है कि इस देश के प्रायः अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और और करीब पांच लाख साठ हजार हमारे देश में गांव हैं । यह भी कहा गया है और विद्युत मंत्री महोदय ने भी इसको माना है कि बिना गांव में बिजली पहुंचाये कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है । ऐसी हालत में इस तरह की संशोधित बिल (विद्युत) एमेंडमेंन्ट का लाना बहुत लाजिमी था । लेकिन मैं माननीय डा० राव को बतलाना चाहता हूं कि विद्युतीकरण के सम्बन्ध में हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है । दूसरे देश हम से बहुत आगे बढ़े हुए हैं । अमरीका को आप देखें । वहां जून 30, 1962 तक 87·7 प्रतिशत फार्म्स को बिजली दी जा चुकी थी । 1975 तक उनका कहना है कि इसको बहुत बढ़ा दिया जाएगा। रशिया के साथ अगर आप अमरीका का मुकाबला करें तो आपको पता चलेगा कि अमरीका उससे भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है । एक अमरीकी किसान करीब करीब 26 अमरीकियों को खिलाता है । यह सब बिजली की वजह से ही है । जितना रशिया में बिजली का कंजम्पशन है उससे तिगुना अमरीका में है । हम जबकि चाहते हैं कि अनाज के मामले में आत्म निर्भर हो जायें और हम चाहते हैं कि हमारी कृषि काफी उन्नति करे तो उसके लिए ऐसे संशोधन की बहुत सख्त जरूरत थी इस मंत्रालय ने बार बार कहा है कि 2अक्तूबर 1969 तक देश के एक लाख गावों को बिजली दे देंगे दो अक्तूबर 1969 को महात्मा गांधीकी शताब्दी है । यदि आप इस में सफल हो गए तो यह एक बहुत बड़ा काम आप कर देंगे । यदि हम दो अक्टूबर 1969 तक प्रायः एक लाख गांवों में बिजली पहुंचना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय बाकी है । दो ढाई साल ही हमारे पास हैं । प्राइवेट कम्पनियों को खत्म करने के लिए आपने एक सुन्दर सुझाव रखा है जिसका मैं अनुमोदन करता हूं । मैं इस सुझाव का हार्धिक समर्थन करता हूं । लेकिन आपको पता होना चाहिये कि ये 214 लाइसेंसीज़ बिजली कम्पनियां कैसे हैं । अभी हमारे मित्र ने बताया है कि वे मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं । मैं बिहार की दो चार कम्पनियों के बारे में जानता हूं । जिन कम्पनियों को बिहार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने नोटिस दिया है उन में से एक दरभंगा लहेरिया सराय इलैक्ट्रिसिटी सप्लाईंग कम्पनी भी है उस नोटिस में उक्त दरभंगा बिजली कम्पनी के संबंध में कहा गया था कि पांच मार्च 1967 तक यह कम्पनी आपको सरकार को दे देनी होंगी । और सही भी है अगर अभी से यह कम्पनियां यह बातें वातारण में फैला रही है कि देखिए डीवैल्यूएशन की वजह से कापर वायर का और और चीजों का दाम इतना आगे बढ़ गया है कि हमें तो काफी दाम मिलना चाहिए । इसके सम्बन्ध में मैं आप को बताऊं कि जिस तरह देशी राज्यों और जमीदारी लेने में आप ने बड़ी तेजी और चुस्ती से काम लिया उसी तरह आप को इन प्राइवेट कम्पनियों के साथ पेश आना होगा नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा । यह जो आप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि 1969 की 2 अक्तूबर तक 1 लाख गांवों में बिजली पहुंचाने का यह प्राइवेट कम्पनियां लक्ष्य पूरा नहीं होने देंगी और डीवैल्यूएशन की बात, कापर वायर की बात और अपने महलों की बात वह करेंगे । इस में भी विशेषकर मैनेजिंग डारेक्टर लोग बहुत चतुर और चालाक हैं । उन के विषय में तो काफी बातें पार्लियामेंट में होती रही हैं । किसी ने यह बताया कि यह शेयर होल्डर्स

को पीछे छोड़कर चाहते हैं कि सारे के सारे बिजली कम्पनियों के मालिक बन जायं ।

जो सेकेंड प्राविजो रखा है सिक्स्थ शिड्यूल का उसमें दिया है :

"Provided further that the licensee shall not be deemed to have failed so to adjust his rates if the clear profit in any year of account has not exceeded the amount of reasonable return by fifteen *per centum* of the amount of reasonable return."

इस को शायद विद्युत मंत्री 20 परसेंट करना चाहते हैं । मैं खामकर इसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि इन्होंने पचासों साल से कन्ज्यूमर्स का काफी शोषण किया है । गांवों की बात आप को बताऊं तो आप हैरत में रह जायेंगे । मीटर्स में लिखा कुछ रहता है और प्राइवेट एलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के लोग लिखते कुछ हैं और बहुत बढ़ाकर चार्ज करते हैं । जब बिजली का बिल पेश किया जाता है और प्रोटेस्ट किया जाता है तो कम्पनी के कर्मचारी कहते हैं कि यह तो गलती हो गई और फिर भी पैसा कभी कभी वापस नहीं करते हैं और करते भी हैं तो उसके साथ इन्टरेस्ट और कई तरह के चार्जेज कभी रिटर्न नहीं करते । मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि नये कृषकों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती । अभी कल परसों हमारे बिहार राज्य के एक बहुत बड़े कृषक नेता पंडित विभूति मिश्र जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं वह कह रहे थे कि बार-बार कहने पर भी वह सुनते नहीं, कृषकों को विद्युत नहीं देना चाहते और मजे की बात यह है कि यह प्राइवेट कम्पनियां आपसे "पावर" लेती हैं, आपसे कम दाम पर पावर लेती हैं और दुगुने तिगुने दाम पर बेचती हैं । तो है क्या ? पुराना उनका मकान है, पोल्स हैं, उनकी कौस्ट्स हैं, उनके कुछ पुराने समय के बायर लगे हैं, लेकिन कन्ज्यूमर्स के साथ जो बेहरमी होती है, जो उनका शोषण होता है वह मैं शब्दों में नहीं रख सकता । इसलिए जितनी जल्दी आप यह काम कर सकें, उतनी जल्दी करें । यह बहुत जरूरी है । इतना कह कर मैं इस संशोधन बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप ने जो तिथि रखी है 2 अक्तूबर, 1969 का, आप को उस पर डटे रहना चाहिए और प्राइवेट विद्युत कम्पनर्स को नेशनलाइज करना चाहिए । 214 लाइसेंसीज को आप अपने जिम्मे ले लीजिए जिससे कि जो ग्राम्य विद्युतीकरण का लक्ष्य आप ने देश के सामने रखा है कि गान्धी शती तक प्रायः 1 लाख गावों को बिजली देंगे, वह आप दे सकें । तब आप किसानों को देखेंगे कि कृषक किस तरह काम करते है और कितना दुगुना प्रोडक्शन करते हैं । धन्यवाद ।

Shri N. Dandeker (Gonda): Mr. Chairman, there are only three matters of public policy and some importance to which I would like to refer in making general comments on this Bill. Otherwise, I think, on the whole, this is a desirable and necessary measure and, it is not in fact too late. For a long time now this sort of measure should have been brought in to straighten out many things which have become ante diluvian in the existing Act.

The three or four matters of some public importance to which I would like to refer in a critical vein are, in the first place, the proposal in clause 2 to amend section 5 of the principal Act. That Section of the principal Act contains a very healthy provision, because it precludes, in so far as it is possible, political patronage becoming rampant. At present the provision about appointment of politicians on State Electricity Boards is this:

"A person shall be disqualified from being appointed or being a member of the Board if he is, or

[Shri N. Dendekar]

within the twelve months last preceding was, a number of Parliament or of any State Legislature or any local authority."

Now, this is a very necessary and salutary rule, and I am astonished that this is sought to be removed despite all that has been said here and outside over the last several years and, in particular, over the last three years about growing corruption all over the country—sometimes central legislators are accused, on other occasions State legislators are accused, officers are accused, the whole bureaucracy is accused. There is a general continuing accusation of growing corruption in the country; and yet when there is an atmosphere of that kind, it is proposed to remove this disqualification from the appointment of ex-Members of Parliament or ex-Members of local legislatures, namely, that they may not be so appointed until at least twelve months have elapsed from the time they ceased to be Members of Parliament or State legislature. I think, Sir, it is very salutary rule as it stands. I am astonished at the reasons that have been advanced in this Statement of Objects and Reasons which read like this:

"Under the existing provisions of the Act, members of Parliament or of the State Legislatures and members of local authorities have to wait for a period of 12 months.. ....."

In fact, that lets the cat out. It is said that they:

".... have to wait for a period of 12 months after they cease to be such members before becoming eligible for appointment as members of the State Electricity Boards."

It is curious: the reason given for changing this is that they have to wait for 12 months. The Government of India is getting very concerned that these gentlemen have to wait for 12 months before they can be given cushy berths. Coming as it does, a few months before the next general elections, and konwing as we all do that some gentlemen from this House and some gentlemen from various State legislatures are going to be dead wood and not likely to stand for elections again; and that many more, far more than the party in power imagines, are going to be routed at the elections, I find that they are to be provided for to the extent possible by reducing the period of waiting before they can be conferred this patronage, this solace of being appointed as members of State Electricity Boards. I suggest Sir, the proposed amendment to section 5 of the Principal Act is thoroughly bad on grounds of public policy. I have no particular gentleman or person in view when I make this comment, I have only the general good of the country and general public policy in view when I say that this is thoroughly bad and ought never to have been brought. I hope the hon. Minister will after consulting the Prime Minister if necessary, withdraw this particular amendment to the existing Act.

The second topic upon which I would like to comment is the one to which Shri Bade has already referred, namely, the proposal that schemes involving capital expenditure of less than Rs. 25 lakhs need not be published at all and that other schemes involving capital expenditure of less than Rs. 1 crore need only be published once. It is a curious proposition. Every one of these schemes involves—I do not say 'unjustly'— tremendous encroachments upon basic rights, property rights and various other things.....

Mr. Chairman: Is it right to bring it on a par with industrial licensing?

Dr. K. L. Rao: I will explain when I reply to the debate.

Shri N. Dandeker: These schemes, Sir, often involve tremendous interference, let me put it at its lowest,— it may be interference for the good, I am prepared to accept it on that

footing—with public and private right of various secions of the people, of farmers, of existing licensees and various other persons of that kind. Also, they involve publication of the intentions and plans of a scheme, the object being plainly—otherwise there is no point in publishing everything that costs not less than Rs. 25 lakhs or a thing that costs more than Rs. 1 crores of any scheme at all—the object of that publication being that wherever anybody has got any objection, wherever anybody has got any suggestions to make, wherever anyone wants....

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, इतना अच्छा भाषण हो रहा है, सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

Shri N. Dandeker: The only purpose of these publications—otherwise I cannot see why schemes costing over Rs. 1 crore should be published twice, why schemes between Rs. 25 lakhs and Rs. 1 crore need be published once.

Mr. Chairman: The qurum is being challenged. He might resume his seat. The Bell is being rung—Now there is quorum. He might continue his speech.

Shri N. Dandeker: As I was saying, the only conceivable object of publishing these schemes, whether once or twice or at all can only be that peoples suggestions, comments and criticism may be invited, may be considered and a final decision taken, which takes into account all those facts and circumstances. Why should it be necessary to do so only when the scheme is over Rs. 25 lakhs, and then to do it only once and when the scheme is over Rs. 1 crore, then to do it twice whereas if the scheme costs below Rs. 25 lakhs nobody's comments apparently are necessary at all. I am unable to comprehend this on any ground whatsoever. The ground suggested is a most extraordinary one, namely, it is expensive; publication twice, once in a draft form and then, again in the final from is expensive. I am astonished that for schemes costing Rs. 15 lakhs, 20 lakhs or 25 lakhs this little publication expenditure—and I am going to give testimony that it results sometimes in a good deal of worthwhile comment and criticism—the expenditure involved in publishing notice twice over is said to be extraodinarily high, is unbearable to the State Government in the case of projects costing up to Rs. 25 lakhs and that they can only bear the cost of one publication if the project costs between Rs. 25 lakhs and Rs. 1 crore. All this is just utterly ridiculous. I am unable to accept that there is any sense of proportion about this in relation to the scheme, its importance, the necessity to invite public comment, the necessity to invite objections to make the scheme better on the one hand and the cost of publication twice or whatever on the other. The whole thing is certainly lacking in any sense of proportion.

I am putting it at its highest. But let me also put it at its lowest. I have one particular case in mind, because I was personally concerned with having to comment upon a scheme. I will not name the State, nor will I give the name of that particular scheme, but it was a cross-eyed scheme. It just happened that I had occasion to criticise it and, I am glad to say, that the scheme was dropped. It was a small scheme costing Rs. 5 lakhs or so; I do not know; but I do not imagine it would have cast more than Rs. 5 lakhs or Rs. 10 lakhs, but the scheme was bad and it was dropped. Am I to understand that the cost of publication of that scheme in draft form and in its final form when finalised and the comments, foolish as they might have been even though I made them, that the whole exercise was a waste of time? Is it suggested that it is not worth the money, it is not worth the paper to publish these schemes and to invite those comments because none of us is so wonderful

[Shri N. Dendekar]

but the State Electricity Board is so wonderful that any scheme of its cannot possibly be bad or improved upon? I must and that all this does not detract from the merits of the schemes at all. I am not saying that all such schemes are cock-eyed. I am not saying that most of the schemes are not necessary. All I am saying is that they could well be improved upon by inviting comments from people affected by the schemes.

The third point to which I object on grounds of public policy, is concerned with amending the clauses concerning the return on capital in the rule or sub-paragraph in the Schedule— it is so complicated that I have always to search for what is in that particular Schedule—it is the Sixth Schedule, 17th paragraph and sub-paragraph 10. This is what is sought to be amended by clause 21, sub-clause (ix) and sub-sub-clause (4), the definition of "standard return" on capital employed. Quite rightly in a public utility, such as is the generation of electricity and the distribution and supply of electricity, the public utility involves a monopoly in given area and it is an accepted doctrine of public policy all over the world that where, because of the public utility situation, that conferring a monopoly to a particular licensee is involved, it is but right that the State should limit the return on capital employed, that the State should define what is "capital employed" define what is the profit and lay down the limit of that profit. That is fair enough and that is what this particular sub-paragraph (10) of the paragraph XVII of Sixth Schedule does. And the rate of return now prescribed is this, that it shall be no more than 2 per cent over the Bank Rate. Today the Bank Rate is 6 per cent; and so the public utilities in the field of electricity should not expect to get more than 8 per cent as fair return. After that, there is a certain limit upto which some flexibility is allowed; beyond that they must get down to reducing their rates so that the public may get the benefit. That is the structure.

But there is now a most extraordinary proposal here in clause 21(ix) (4) the details of which I will not refer to now, which seeks to perform two extraordinary antics when the situation to be faced is a perfectly straightforward and simple one. The first antic is this. Every electricity company will now have to divide its capital at charge into two parts, one invested up to such and such date, and the other invested thereafter. And why is this curious business of splitting up the capital at charge into these two parts? For this extraordinary reason, that the capital already at charge they intend should get a lower return of only 7 per cent and only the new papital should earn a return of 8 per cent. They intend to reduce the present return of 8 per cent to 7 per cent and only capital at charge that comes in after a particular D date will get a return, as before, of 6 plus 2, that is, 8 per cent.

Is the Minister in charge of this subject living completely divorced from current economic circumstances. Has he not read the Eonomic Survey? Has he not read the Finance Minister's speech on devaluation? Has he not read the recent Supplement to the Economic Survey? Has he not known that for the last two or three years the capital market has been so dull that even at 7 per cent or 8 per cent for Debentures and even at 10 per cent for perference capital, it is difficult to get capital coming in? And what does he want to do? He wants to go comletely against the policy of the Finance Minister, the policy of the Government of India as a whole, the basic reason for devaluation, at any rate one of the basic reasons, namely to revive equity market. He wants to reduce the return on capital already invested to 7 per cent.

Today I can put in Rs. 100 or Rs. 1,000 or whatever amount I wish in the Unit Trust of India and get 7 per cent and take no risk whatsoever. The last dividend declared by the Unit Trust is 7 per cent. I can put in Rs. 15,000 today at 7 per cent, and get just a little over Rs. 1,000 by way of return I get safe investment, on which I get 7 percent and Rs. 1,000 of that return is totally excluded from my total income for purposes of taxation. Am I to believe that this Minister really wants expansion of the industry, that he wants rehabilitation, modernisation and development? What does he want?

14 hrs.

If he really wants those things, is this the kind of rate of return that he is thinking of as realistic? On grounds of public policy, Sir, on grounds of policy announced by Government themselves, on grounds such as those which the Government have themselves been urging—there is a statement in the *Economic Survey* which I will read out when I come to the clauses, where it says that savings are going down; in particular, that people are more and more being attracted by fixed interest investments than risk capital,—how can one support the proposal which the Minister makes here, that is going to cause the deathknell of any risk capital coming in here when fixed interest returns like those of the Unit Trust and on five-year deposits are going to fetch 7 per cent, 7-1|2 per cent and 8 per cent?

These are the three major policy comments I would like to make on this Bill. I will go into the details when the time comes for clase-by-clause consideration.

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं अपने मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस बिल को वापस ले लें क्योंकि इस बिल से किसानों का कोई फायदा नहीं है । जब तक इस बिल में यह बात नहीं आती कि सारे देश में बिजली का एक रेट रहेगा तब तक इससे किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है । इस बिल के क्लाज 11 में कहते हैं कि :

"In fixing the uniform tariffs, the Board shall have regard to all or any of the following factors, namely:—

(a) The nature of the supply and the purposes for which it is reqired;"

इसी के पार्ट (बी) में कहते हैं कि :

"the co-ordinated development of the supply and distribution of electricity within the State in the most efficient and economical manner, with particular reference to such development in areas not for the time being served or adequately served by the licensee;"

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस बिल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि जो एलैक्ट्रिसिटी देश में पैदा होगी उसका कितने परसेन्ट देश के खेतिहरों को देंगे, कितने परसेन्ट रोजगार को देंगे, कितने परसेन्ट शहरों में जो लोग मौज करते हैं उनको देंगे, कितने परसेन्ट एअर कंडिशनिंग के लिये देंगे और कितने परसेन्ट फूड प्रिजर्वेशन के लिये देंगे । इसके माने यह हैं कि किसानों को जो बिजली मिलनी चाहिये वह उसकी आवश्यकता के के अनुसार नहीं मिलेगी । मैं चाहता हूं कि अगर किसानों के प्रति सरकार की ईमानदारी है तो इस बिल को वापस लिया जाये और दूसरा बिल लाया जाये ताकि किसानों को आज जो तकलीफ है उसको दूर करने वाली चीजों को उस बिल में जगह मिल सके ।

रेट्स के बारे में डा० राव ने अपनी स्पीच में कहा कि वह बेचारे चाहते तो थे कि सारे देश में एक रेट हो लेकिन चूंकि एक ग्रिड सिस्टम नहीं है इस लिये वह ऐसा नहीं कर सके । मैं कहना चाहता हूं कि अगर सारे देश के लिये एक ग्रिड सिस्टम नहीं है तो आप सबसिडी का सिस्टम रखिये । जिस स्टेट में

[श्री विभूति मिश्र]

में चार्जेज ज्यादा हों वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे । आज सेंट्रल गवर्नमेंट गेहूं को सब्सिडाइज करती है क्योंकि खाने पीने की दिक्कत है, और चीजों के लिये भी वह सब्सिडी देती है, बड़े बड़े कारखानों को सब्सिडी देती है, हमें याद है कि टाटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी जब वह घाटे में जा रहे थे, लेकिन किसानों को कुछ भी देने के लिये आज वह तैयार नहीं है । आज कारखानों के लिये जो बिजली दी जाती है उसके रेट कम हैं, लेकिन किसानों को, जो कि बिजली से पानी पैदा करता है और पानी पैदा करके खेती पैदा करता है और अनाज सरकार को देता है उसके लिये सरकार कुछ भी करने के लिये तैयार नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि इस बिल के आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि बम्बई एक कंम्पैक्ट एरिया है और दूसरी जगहों पर बिजली का खर्च ज्यादा बैठता है इस लिये बम्बई में बिजली का रेट ज्यादा नहीं होना चाहिये । सभापति महोदय, जहां पर आप बैठे हुए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है "धर्मचक्र प्रवर्तनाय" अर्थात् इस देश में धर्म का चक्र चल रहा है, दूसरे हमारे संविधान में लिखा हुआ है : "**सोशल जस्टिस, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी** ।" मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित है कि चूंकि बम्बई में कंसेंट्रेशन आफ पापुलेशन है, वहां पर बिजली का रेट सस्ता होगा, इसलिये उन को तो सस्ती दर पर बिजली मिलेगी लेकिन गांव गांव में किसान बसे हुए हैं, जो कि खेती बाड़ी के एरिया में रहते हैं इसलिये उनको बिजली महंगी मिलेगी । आप कहते हैं कि बम्बई हाईकोर्ट का फैसला हो गया इस लिये हमारे डा० के० एल० राव घबरा गये । आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो कुछ दिया हुआ है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बम्बई हाईकोर्ट का फैसला हो गया था तो तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वहां आप को आना चाहिये था । सुप्रीम कोर्ट वाले कम्पिटेंट अथारिटी हैं संविधान की परिभाषा के लिये, वह आप को संविधान की सही बात बतलाते । लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में मामले को नहीं लाये । आपने बम्बई हाईकोर्ट की तय की हुई बात को मान लिया हालांकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सब के साथ जस्टिस होगी । आज बम्बई में ज्यादा लोग रहते हैं इसलिये आप कहते हैं कि उनके साथ जस्टिस होनी चाहिये । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस रेट से बम्बई आगे पहुंचा है सैकड़ों वर्ष के बाद भी गांव वाले उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं । आज सब जगह पर सारी पार्टियां वोट्स के लिये गांवों की ओर जा रही हैं, बम्बई के भी बड़े बड़े कार्यकर्ता गांवों की ओर जा रहे हैं, हमारी पार्टी भी सोचती है कि आज वह गांवों की तरफ जायें । आज कलकत्ते के बड़े बड़े नेता, बम्बई के बड़े नेता कहते हैं कि हर पार्टी के जिन्दा रहने के लिये जरूरी है कि वह गांवों की ओर चलें क्योंकि गांवों में वोट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन जब बिजली देने का सवाल आता है तो वही लोग निर्णय करते हैं कि शहरों को सस्ते रेट पर बिजली मिले । बम्बई हाईकोर्ट का हवाला देकर यह बिल अपने आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स में यह लिख देता है । ऐसा नहीं होना चाहिये । अगर सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला होता तो न्याय का फैसला होता और गवर्नमेंट भी सोचती लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कुछ सोचना नहीं सिर्फ बम्बई हाईकोर्ट का हवाला भर कर दिया ।

हिन्दुस्तान में कुछ ऐसी एरियाज़ हैं जहां बिजली की अधिक सुविधा है खेतिहरों के लिये और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां बिजली की सुविधा नहीं है । इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि जो एरिया पिछड़े हुए हैं जहां पर कि अभी बिजली नहीं है, उनको बिजली दी जायेगी । अगर उनको बिजली

नहीं दी गई तो अच्छे तगड़े लोग होते हुए भी वे लोग पीछे रह जायेंगे । आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका ज्यादा ख्याल किया जाता है, खाने पीने की सहूलियत भी उस को ज्यादा दी जाती है, लेकिन जो घर में मोटे तगड़े रहते हैं उनका ख्याल जरा कम किया जाता है । मगर हम अपने देश में देख रहे हैं कि बिजली के मामले में जो मोटे तगड़े थे वह मोटे तगड़े होते चले गये और जो पतले थे वह पतले ही होते चले गये । इस बिल में इस चीज को ठीक करने के लिये कोई गुंजाइश नहीं है ।

सभापति महोदय : पहलवानों को ज्यादा खिलाया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : पहलवानों को ज्यादा खिलाया जाता है बाजी मारने के लिये ताकि वह पैसा कमा करके सब को दें । लेकिन आज हमारे देश में जो पैसा कमाते हैं उनको कौन देता है । आज देश में किसी जगह बिजली का रेट 6 पैसा है, कहीं पर 7 पैसा है और कहीं पर 8 पैसा है लेकिन अगर आप बिहार में चल कर देखें तो दक्षिण बिहार में उसका रेट 18 पैसा है और उत्तर बिहार में 22 पैसे से लेकर 28 पैसे प्रति यूनिट तक है । पूर्वी उत्तर प्रदेश भी हम से मिलता जुलता है । लेकिन इस बिल में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है कि बिजली की सप्लाई के मामले में सारे देश के साथ एक सा बर्ताव किया जायेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल किसी भी काम का नहीं है और सरकार को चाहिये कि वह इसको वापस ले ले ।

इसके अलावा स्कीम्स के बारे में कहा गया है कि बोर्ड जो है वह कैसला करे, लेकिन बोर्ड का कांस्टिट्यूशन कैसे होगा इसका कहीं पता नहीं है । क्लाज 6 में में लिखा है कि ऐक्ट के सैक्शन 29 में यह लिख दिया जाये :

"A scheme prepared for any area under section 28 may, subject to the provisions of this section, be sanctioned by the Board either generally or in respect of any part of the area and where a scheme has been sanctioned in respect of part of the area, it may subsequently be sanctioned in respect of other parts of that area."

मैंने स्टेट्स में भी देखा है कि बिजली उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स में रहते हैं और जिनकी थोड़ी बहुत चलती है । यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गरीब किसान को भी बिजली मिल । आपने अब सीलिंग कर दी है । आप सोच सकते हैं कि देहातों में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ की जोत है, दो एकड़ की जोत है या चार एकड़ की जोत है । उन आदमियों को सुबह से शाम तक खाने पीने की भी फुर्सत नहीं है । जिस को अपने काम धन्धे से ही फुर्सत नहीं है वह कैसे किसी को अपनी स्कीम देने के लिये जायेगा । यह लोग तो ऐसे आदमी हैं जो कलेक्टर से जल्दी मुलाकात भी नहीं कर सकते । इसलिये स्कीम रक्खे जाने के बजाय यह जरूरी है कि सरकार ऐसी एरिया में बिजली लगाये जहां पर बिजली नहीं है । वहां पर बगैर किसी से पूछे हुए ही उसको लगाना चाहिये बजाय इसके कि जहां पर बिजली है वहां पर उसको ले जाये । सेक्शन 29 के (ए) भाग में यह एक बड़ी भारी खामी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय इसकी तरफ ध्यान दें । यह पानी के महकमे का हाल जानने वाले भी हैं और इर्रीगेशन को भी जानते हैं । बिजली से भी इर्रिगेशन होता है इसको भी वे जानते हैं । इसलिये उन को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिये । प्राइवेट कम्पनियां 214 हैं । उनमें शायद 120 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है । ये कम्पनियां बहुत धांधली मचाती हैं । आपके सरकारी डिपार्टमेंट भी बहुत धांधली मचाते हैं । अगर एक बिल का पेमेंट कर दिया गया होता है तो दूसरे बिल में भी उसको शामिल कर दिया जाता है । और दुबारा उसका पेमेंट ले लिया जाता है । बरौनी से बिजली

[श्री विभूति मिश्र]

जाती है। वहां पर भी मैंने देखा है कि बिजली के एक बिल का पेमेंट कर दिया जाता है तो फिर से उस को चार्ज कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बिजली महकमा किसी के साथ इस तरह का अन्याय करता है तो जब वह पैसा उसको वापिस करे तो सूद सहित उसको वापिस करे। लेकिन यहां हम देखते हैं कि उसको कोई पनिशमेंट ही नहीं है। जो व्यापार चलाता है और जो धांधली करता है उसके लिए तो पनिशमेंट है लेकिन इन कंपनियों के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। इनके लिए भी कुछ दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम किसी से अन्याय करके उससे पैसा ले लें तो उसको रिफण्ड करने की, सूद सहित, व्यवस्था होनी चाहिये। बहुत आदमी है जोकि बिजली महकमे से परेशान हैं। दिल्ली से एक साहब गए थे मोतीहारी। वह सैंट्रल गवर्नमेंट के आदमी थे। उन्होंने वहां पर लोगों की एक मीटिंग में कहा था कि बिजली के महकमे से हम भी परेशान हैं। यह बात उन्होंने पब्लिक में कही थी। जब आप भी समझते हैं कि इस तरह की बात है तो आपको इसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिये। जब एक बार कानन बन जाता है तो अगर हम किसी बात को कहते हैं तो लोग कहते हैं कि कानून आपने ऐसा बना दिया है कि कुछ नहीं हो सकता है और हम उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं समझता हूं कि कानून आपको ऐसा बनाना चाहिये कि उस में इस तरह की चीजों की गुंजाइश रहे, उपभोक्ताओं की जो तकलीफें हैं उनका निवारण हो सके। जो लोगों की तकलीफें हैं उनको दूर कर लोगों को सैटिसफाई किया जाना चाहिये।

मैंने देखा है कि कारखानेदारों को बिजली की जरूरत होती है या पानी की जरूरत होती है तो पहले उनको मिल जाता है और काश्तकारों को नहीं मिलता है। सरकारी जो महकमें हैं ये कारखानेदारों को बहुत जल्दी सहूलियतें दे देते हैं, काश्तकारों को नहीं देते हैं। किसानों में जो छोटे किसान होते हैं उनको इसलिए नहीं मिल पाती है कि उनकी पहुंच नहीं होती है, आधी धोती वे पहने रहते हैं नंगे शरीर रहते हैं, उनके पावों में जूते नहीं होते हैं, उनके पास छाता नहीं होता है। वे पहुंच नहीं पाते हैं सरकारी महकमों में जबकि जो कारखानेदार होते हैं उसके पास मोटर होती है और वह धड़ाक से पहुंच जाता है और उसका काम हो जाता है। अगर सरकार चाहती है कि इस बिल को किसानों के हित में बनाया जाए तो जरूरत इस बात की है कि देखा जाए कि किस तरह से किसानों का हित हो सकता है। हमारे इकोनोमिक का जो हालत है उसको हम देख चुके हैं। वह बहुत बिगड़ी हुई है। अगले साल के लिए अंदाजा लगाया गया है कि अठारह मिलियन टन की शार्टेज होगी। अगर वर्षा ठीक हो गई तो हो सकता है कि कम शार्टेज हो। लेकिन आज यह अन्दाजा है कि अठारह मिलियन टन की शार्टेज होगी। मैं चाहता हूं कि सरकार यह निश्चित कर दे कि किसान को इतनी बिजली मिलेगी और इसका वह बटवारा कर दे। उसका रेट क्या होगा इसको भी वह निश्चित कर दे। सारे हिन्दुस्तान भर में एक ही रेट होना चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक रेट होना मुश्किल है तो सरकार उसको सबसिडाइज करे और सस्ते रेट पर किसानों को बिजली दे।

Shri Priya Gupta (Katihar): The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power has brought forward this Bill before the House. He is an Engineer and I am very proud that he is taking full interest in the works attached to the Ministry. But I expected from him that in the context of the discussion in the House and in the context of the assurances given outside, this Bill should have been a bit more comprehensive, accommodating the question of common grid, the question of rate of electricity itself and the

question of premium assured to the villagers in the shape of subsidised amounts, in the shape of less rates, for the purpose of electrification and for running electrically driven tubewells for watering paddy fields over there. All these things should have also been incorporated in this Bill.

Whenever the Government comes forward with an amendment of any Act, there must be certain justification. I do not bring in any insinuation here, when I make my observation regarding one of the changes suggested in the Bill about the eligibility of the Members of Parliament and the Members of Legislative Assemblies just after they cease to be so for the membership of the State Electricity Boards. Formerly, prior to this proposed amendment, there was a condition that an M.P. or an M.L.A., after he ceases to be so, must have to pass twelve months before he can be considered for the purpose of membership of the State Electricity Board. Now, I am led to believe that since the decision is that about one-third of the total number of existing legislators will be eliminated from giving the tickets for the next General Elections, the intention of the Government is to give them a provision in the State Electricity Boards because, if there is no pay, at least there will be T.A. and other facilities. I may be wrong in my assessment. But this is what has led me to believe.

Then, there is the question of publications in the gazettes. I want to know how the amount of Rs. 25 lakhs has been fixed as a limit. Why not Rs. 15 lakhs or Rs. 12 lakhs or Rs. 10 lakhs? What is the reasoning behind this? I do not mean any insiuation or any bad intention. But that creates a confusion as to what is the meaning in having Rs. 25 lakhs level and Rs. 1 crore level. The hon. Minister may clarify that when he replies to the debate.

Under the Indian Limitations Act, the payments cannot be recovered beyond a period of three years from the date of claiming them. The period is going to be extended. I do not understand the implication of it. It may be the dues are in arrears. Why is it that the State Electricity Boards are not prosecuting them in time? Where is the lacuna? Where is the defect in the machinery over there. Why can't they check that the arrears do not fall beyond the period of three years? That is my point. Is it just to garb the delinquency of the officers in-charge over there that this has been done? Is it because the Government is losing heavy amounts and all this is due to the delinquency of certain officers over there whom they do not want to penalise or punish because a deterrent punishment would have to be given to them for this serious lapse? It is with retrospective effect as far back as one year or something like that. I seek a clarification from the hon. Minister on this.

Regarding the percentages to be kept in the reserve fund, of course, that is a question of economics as Mr. Dandekar and somebody else pointed out who may be interested in capitalists over there. But what I mean to say is that there should have been a reason shown in the preamble as to why this has been done.

Lastly, I want to submit that a common grid system, as promised in the House also, would have given us a chance to provide electrification at a cheaper cost to the villages. I come from one of the most backward places in north Bihar. The Bihar Government cannot afford to spend more money. The management of the Bihar State Electricity Board is such that the backward people over there, for the purpose of irrigation and tubewells, do not get electricity even today. I am talking of the Katihar constituency of the Purnia District and other backward villages. There would have been a granary of foodgrains over there if there would have been a provision for tubewells running on electricity and the electricity would

[Shri Priya Gupta]

have been given to the villages concerned. If the State Government cannot manage it, the Central Government should subsidise it. Agriculture is the primary thing. Even the Planning Commission is just finalising the scheme on the basis of such premium on agriculture itself. Keeping this in view, the Ministry should think of bringing certain changes to the Act. Some subsidy should be given for the villagers for making electricity available to them at a lower rate which they can afford to pay.

Coming to the workers of the Electricity Board, may I suggest that, with devaluation, there has been a cut straightaway in the real wages of the workers to the extent of 30 per cent.? As you all know, the workmen are wage-earners. Mr. Dandeker is smiling over what I said; he might be saying that devaluation has not affected the internal economy. But I say that it has affected them.

Shri Warior (Trichur): He said that rising prices had already made the cut.

Shri Priya Gupta: To add to that, devaluation has made another cut to the extent of 30 per cent to the real earnings of the workers. Since they are wage-earners, they have got no other source to compensate them; they have got to suffer for it. So I would say that there should be an attempt to give them an *ad hoc* increment to compensate them for this cut and then they can consider whatever dearness allowance is to be given.

In regard to bonus to the workers, there should be some consideration by the State Electricity Board.

Lastly, there is a suggestion for taking over the private companies. The private companies running there should be nationalised and if that is done, there will be much more uniformity in rates, returns and everything, and the interests of the particular groups of capitalists will be eliminated. The difficult situation in the supply of electricity itself would also ease in the near future.

In the last I would like to suggest changing over from coal to diesel oil for the purpose of generating steam for running the prime movers of generating stations. The boilers run by coal are more cumbrous—the machinery itself—and are more costly than oil-run boilers. If diesel oil is used for running the boilers, the capital costs would be much less. So this point should be considered. Moreover, the utilisation of solar energy for the purpose of generation of electricity should be thought of because in that case we would not spend much money for generation of electricity. Today it is an aid for electricity.....

These are the points which I submit for the very active consideration of the hon. members. With these words, I conclude.

Mr. Chairman: Before I call upon other members to speak, I would like to say that I have received a number of chits. Many members are interested in speaking on this subject. I have to keep in view two things: Parties and also States. Since the legislation brings within its purview the entire country, it is necessary that representatives from all the States participate in the discussion.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : यू० पी० सबसे बड़ी स्टेट है। इसको समय मिलना चाहिए।

श्री ना० प्र० यादव (सीतामढ़ी) : चेयरमैन साहब, बिहार स्टेट बहुत बड़ा है, इसलिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए।

Mr. Chairman: Three gentlemen from Bihar have spoken. So it would be better if I ask a member belonging to another State to speak. I, therefore, call Mr. Sinhasan Singh.

Shri Warior: In this, the worst affected State is Kerala.

Mr. Chairman: I know that.

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): विरोधी दल की तरफ से जो सदस्यों की अयोग्यता को दूर करने के बारे में सुझाव आये है कि साल भर की जो अवधि थी वह हटायी जा रही है उस के साथ सहमत न होते हुए भी मेरा यह गवर्नमेंट को सुझाव होगा कि कम से कम जो इन्सिन्युएशन का मौका उन को मिल गया है कि शायद इस गरज से यह किया जा रहा है कि हारे हुए सदस्यों को स्थान मिल जाय.....

श्री प्रिय गुप्त : या जिनको टिकट नहीं मिला है।

श्री सिंहासन सिंह : वह भी आ गया उसी के साथ।

तो किसी चीज को लाने का उपयुक्त समय होता है। चूंकि यह चुनाव का समय है तो इस समय कोई ऐसा अमेंडमेंट आवे, इसकी जरूरत नहीं है, इसको ज्यों का त्यों रहने दिया जाय तो हमारी ही प्रेस्टिज में कुछ बढ़ोत्तरी होगी, उसमें कोई कमी नहीं आयेगी। इसलिये इस को जोर देकर पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अब तक जो अयोग्यता साल भर की थी, उस को हटा दिया जावे खास कर ऐसे मौके पर जबकि चुनाव बहुत करीब है और जैसा कि कहा जा रहा है कि किस कारण यह किया गया है, इस से रूलिंग पार्टी पर लोगों को आक्षेप करने का मौका मिलेगा, यह मौका नहीं मिलना चाहिए।

अब इस विधेयक के बारे में मेरा विचार है, सन् 48 का यह एलेक्ट्रिसिटी बिल पास किया हुआ है। बहुत समय हो गया। उस समय की अवस्था में और आज की अवस्था में बहुत अन्तर है। उचित तो यह था कि सन् 66 के वर्ष में हम उस विधेयक में आमूल परिवर्तन करते। उस में कई अथारिटीज हैं। इसमें भी अथारिटिज का जिक्र है। हम ने देखा कि कई अधिनियमों में हमको हर साल में दो बार तीन बार संशोधन करने की नौबत आ जाती है। इस का कारण यही है कि हम हर एक चीज को एक स्थान पर देख कर के उस को सुधारने की व्यवस्था करते हैं। अगर कुछ समय का ख्याल कर के सुधार की व्यवस्था ठीक तरह से की जाय तो जो विभूति मिश्र ने आक्षेप किया है उसका मौका नहीं मिलता। अब तो इस वक्त जो हमारे सामने है उसी पर हम विचार कर सकते हैं।

दण्डेकर साहब ने एक बात कही 25 लाख और एक करोड़ के ऊपर। इसको हमने देखा दफा 28 स्कीम के अन्दर है। उस स्कीम के अन्दर काफी चीजें हैं जो बोर्ड बनेगा उस को ट्रांसमीशन लाइन ले जाना है, नयी सेटिंग करना है, प्राइवेट कम्पनियों की लाइन को इस्तेमाल करना है। यह एक ही प्रकार की चीजें हैं और इस के अन्दर यह है कि जो 15 लाख के ऊपर की स्कीम है यह बगैर स्टेट गवर्नमेंट की स्वीकृति के नहीं होगी। 15 लाख की सीमा पड़ी हुई है। अब दफा 29 में या कि स्टेट गवर्नमेंट की पन्द्रह लाख के ऊपर स्वीकृति होने के बाद उन को दो बार पब्लिश करना पड़ रहा था। इसमें आप ने तीन बार कर दिया। एक 25 लाख के नीचे, कोई पब्लिसिटी नहीं, 25 लाख से 1 करोड़ तक एक बार की पब्लिसिटी और एक करोड़ के ऊपर जैसा था वैसा ही रहा। हमारा ख्याल है कि दण्डेकर साहब को इस में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लाइन ले जाना है और जो दिक्कत है, मैं अनुभव कर रहा हूं खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रिहैड का बिजली घर बना इस अभिप्राय से कि सारे पूर्वी जिलों को, बिजली दी जायगी और काफी बड़ा बिजली घर बना। लेकिन आज अगर बिरला साहब उस बिजली को न लिए होते, जिसके दिये जाने के मैं विरुद्ध था, लेकिन वह नहीं लिये होते तो सारी

[श्री सिंहासन सिंह]

बिजली बेकार पड़ी रहती केवल ट्रांसमिशन लाइन के बनने के कारण। आज हमारे गोरखपुर में 76 हजार या 60 हजार बिजली वहां से आया है। लेकिन वह भी बिजली वितरण नहीं हो पा रही है क्योंकि लाइन नहीं बनी है। लाइन न बनने के कारण यह है कि जो आपका विभाग है उस के अन्दर दो विभाग बन गए हैं।

मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, वह बात कर लें तो शुरू करूं। सुनाना तो मुझे मिनिस्टर साहब को है आप के थ्रू, अब उन का दिमाग सुनने में न हो, तो हमारा कहना बेकार है।

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब का कसूर नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि आप के दो विभाग हैं—एक बिजली बनाने वाला और दूसरा बिजली ट्रांस्मिट करने वाला, लेकिन दोनों में आज कोई कोआरडिनेशन नहीं है। बिजली बनाने वाला खड़ा कर दिया लेकिन ले जाने वाला सुस्त पड़ा हुआ है, परिणाम यह होता है कि बिजली बन कर तैयार है, उपभोक्ता को ज़रूरत है लेकिन उस के पास लाइन नहीं है।

आप कहते हैं कि लाइन ले जाने का सामान नहीं है, मैटीरियल नहीं है। एक दफ़ा आप ने कहा था कि उस दिक्कत को हम ने सहल कर दिया है, लकड़ी के खम्बों से ले जा सकते हैं। मुझे स्मरण है कि गोरखपुर में कई लाख के लकड़ी के खम्बे लिये गये, लेकिन बाद में फेंक दिये गये, नहीं लगाये गये और अब लिये भी नहीं जाते। मैंने रेलवे मिनिस्टर से कहा था कि वहां पर अरबों की रेल-लाइनें पड़ी हुई हैं, जोकि एक प्रकार से वहां पर फैंकी हुई हैं। न वह नीलाम करते हैं और न कोई लेने वाला है, पड़ी सड़ रही हैं। आप चले जाइये, लाइन की पटरियों के साथ हर जगह पटरियों को उखाड़ कर डाला हुआ है, उन को इस काम में लाया जा सकता है। कर्जा लेने के लिये तो हमारे मिनिस्टर अमरीका और जर्मनी दौड़ जाते हैं, लेकिन घर में जो सामान बेकार पड़ा हुआ है, उस का प्रयोग नहीं हो रहा है। आप को चाहिये कि आप रेलवे विभाग को कांटेक्ट करें—कि भाई, मुझे ट्रांस्मीशन लाइन के लिये तुम्हारे पास जितनी रेल पटड़ी उखड़ी पड़ी है, उन को नीलाम नहीं करो, मुझे दे दो। अगर गवर्नमेंट लेवल पर इस मामले को लिया जाय तो ट्रांस्मीशन लाइन की व्यवस्था हो सकती है। इसलिये यह कोआरडीनेशन जरूर होना चाहिये।

14.32 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जहां पर भी बिजली बन रही है, बिजली बनने के साथ साथ ट्रांस्मीशन लाइन की, खम्बों की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये, नहीं तो वह बिजली बेकार पड़ी रहती है। आज भी आप रिहन्द को ले लीजिये, वह घाटे में चल रही है क्योंकि बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है, पांच टरबाइन में से वहां दो-या-तीन काम कर रहे हैं, अभी भी एक-दो वहां पर बेकार पड़े हुए हैं। हमारा कैपिटल जो इस के अन्दर बंधा हुआ है, उस को बढ़ाने का यही तरीका है कि आप ट्रांस्मीशन लाइन को जहां तक बढ़ा सकें, बढ़ायें। इस में अगर कोई दिक्कत है सामान मिलने की, तो रेलवे मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कर के आप उन से लेवें।

दूसरी तरफ़ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं सैक्शन 49 की तरफ़ जिस में आप ने एक बड़ा अच्छा परिवर्तन किया है। जिस रूलिंग का इस में जिक्र किया गया है, हमारे विभूति मिश्र जी ने शायद उस रूलिंग को और आप के प्राविजन को गलत समझा

है । आप ने बम्बई हाई कोर्ट के किसी रूलिंग के आधार पर इस को बनाने की कोशिश की है । बम्बई हाई कोर्ट ने कहा है कि आप के इस सैक्शन में ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है कि आप सब को एक टैरिफ दे सकें, उस को दूर करने के लिये आप ने यह किया है । इस का उद्देश्य बहुत अच्छा है और आप ने यह जो परिवर्तन किया है, यह ठीक है, लेकिन इस के साथ आप ने जो क्लाज लगा दी है, प्रोविजो लगा दिया है, इस से बात बिगड़ जाती है । जहां पर आप ने यह अमेन्ड किया है कि टैरिफ एक किस्म का बनेगा एक एरिये में, वहीं पर यह भी दे दिया है कि अगर वह अथारिटी चाहे तो टैरिफ अलग-अलग भी दे सकते हैं ।

> "Nothing in the foregoing provisions of this section shall derogate from the power of the Board, if it considers it necessary or expedient to fix different tariffs for the supply of electricity to any person not being a licensee...".

आप ने बोर्ड को अधिकार दे दिया कि वह डिफरेण्ट टैरिफ भी दे सकती है । इस का लाभ किस को मिलेगा, काश्तकारों को नहीं मिलेगा, इस का लाभ मिलेगा दाण्डेकर साहब के साथियों को, जो मालदार हैं, उन को बिजली सस्ती हो जायगी । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि पैरा 3 को आप निकाल दीजिये । श्री दाण्डेकर साहब राजी हो जायें तो एक टैरिफ हो सकता है, यदि आप इसे निकाल दें । किसी तरह की पावर आप बोर्ड को डिस्क्रीमिनेशन की न देवें । जिस एरिये में जो रेट हों, सब को एक तरह का रेट मिले, चाहे वह काश्तकार हो, चाहे इण्डस्ट्रीयलिस्ट हो । आप जो यह लूप-होल छोड़ रहे हैं कमोबेश करने का, इस से वह टैरिफ नहीं रह जायगा बल्कि एक किस्म की जलन होगी और नतीजा यह होगा कि उस में फर्क पड़ जायगा ।

दूसरी तरफ़ आप ने रिकवरी के लिये तीन वर्ष की मियाद रखी है, गवर्नमेंट के लिये यह 60 वर्ष थी, लेकिन बोर्ड को कोमर्शिल बोडी होने के कारण तीन वर्षों में आप ने रुपया वसूल करने के लिये तो अच्छा किया है लेकिन आप ने इस में दावा करने का प्रावीजन कर दिया है । अभी तक इस के अन्दर गवर्नमेंट मशीनरी होने के कारण उन को लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करने का अधिकार था, लेकिन अब बोर्ड को इस अमेण्डमेण्ट के मुताबिक दावा करने के लिये जाना पड़ेगा और मुकदमा लड़ना पड़ेगा । यह रकमें बाकी किस की तरफ़ हैं, छोटे-छोटे कनज्यूमर्स की तरफ़ बाकी नहीं हैं, बाकी हैं करोड़पतियों की तरफ़, मिल मालिकों की तरफ । आप यू० पी० में कानपुर में जाइये, वहां किसी पर 10 लाख बाकी है और किसी पर पचास लाख बाकी है । हमारे यहां बिजली का बिल अगर एक महीने में न दिया जाय तो नोटिस दिया जाता है कि डिसकनेक्ट कर दिया जायगा, लेकिन उन के यहां काम डिसकनेक्ट नहीं होता है, उन का काम तेजी से चलता रहता है । इस डिसकनेक्शन के रूल को क्यों न डालमिया, बिरला, टाटा, सब पर समान रूप से लागू किया जाता है, क्यों घुरहु पर, मनोहरु पर लागू किया जाता है । आज उन की तरफ़ लाखों रुपया बकाया है, तीन वर्ष, दो वर्ष पर दावा करें तो पावें, नहीं तो टाइम-बार्ड हो जाय, क्या करें, साहब, भूल गये, टाइम-बार्ड हो गया । इसलिये उचित यह है कि जितने गवर्नमेंट के बोर्ड बने हुए हैं, इन को वसूली के लिये लैण्ड-रेवेन्यू के अधिकार दिये जायें, जो कलैक्टर को रेफर कर दिया जाय और वह वसूल करे । ताकि दावा करने की नौबत न आवे । लेकिन इस के साथ यह भी होना चाहिये कि किसी की तरफ एक-दो महीने से ज्यादा का पैसा बकाया न हो, जिन की तरफ़ बकाया रह जाय, उन की बिजली डिसकनेक्ट कर दी जाय, ऐसा इस में प्रावीजन होना चाहिये ।

[श्री सिंहासन सिंह]

आज हमारी गवर्नमेन्ट का और इरिगेशन मिनिस्टर साहब का भी काफ़ी जोर कृषि की तरफ़ है । कृषि की काफ़ी तरक्की की जाय, हर तरह से तरक्की की जाय क्योंकि देश का भाग्य आज उस के साथ लगा हुआ है । डिवैल्यूएशन का भार भी कृषि पर आधारित है, लेकिन उस के लिये कर क्या रहे हो । बिजली के लिये आप ने बड़ी मेहरबानी की कि 12 पैसे यूनिट पर देने के लिये हर स्टेट को आप ने कहा है, अधिक जो होगा वह आप देंगे, स्टेट गवर्नमेन्टों में भी अभी यह कहीं पर लागू हुआ है और कहीं पर नहीं भी हुआ है । आप गिरिड बनाने जा रहे थे, अभी वह नहीं बना है, इस बिल में भी उस का कोई जिक्र नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहता हूं । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यू० पी० सरकार ने एक नियम बनाया है कि सरकारी ट्यूब-वैल से चार फर्लांग के अन्दर किसी प्राइवेट ट्यूब-वैल को बिजली से नहीं चलने दिया जायगा, डीजल से भले ही चले, उस में कोई हर्ज नहीं है । मैंने गवर्नमेंट को इस के लिये लिखा और आप को भी लिखा, लिखने के बाद गवर्नमेन्ट की सब-कमेटी बैठी, उस सब-कमेटी ने बड़ी मेहरबानी कर के चार फर्लांग को तीन फर्लांग कर दिया, लेकिन साथ ही एक डण्डा लगा दिया कि बिजली से चलाने वाले को सबसिडी नहीं मिलेगी । आप चाहते हो कि कृषि को पानी मिले, बिजली से पानी मिले, डीजल से पानी मिले, मगर बिजली से पानी देने वाले को सबसिडी नहीं देंगे, क्योंकि सस्ती बिजली के पानी से एक बार की बजाय तीन बार, चार बार खेती करेंगे और अधिक अन्न उपजाया करेंगे । अधिक अन्न उपजाने की बिजली के द्वारा कोई स्कीम होगी तो आप सबसिडी नहीं देंगे । जहां तक डीजल द्वारा इंजन चलाने की बात है पांच हार्स पावर तक, वहां पर कहा गया है कि पचास परसेंट सबसिडी देंगे । डीजल वाले को तो पांच हार्स पावर तक सबसिडी मिल गई लेकिन अगर किसी ने बिजली लगा ली तो एक पैसा सबसिडी का उस को नहीं मिलेगा । डीजल की जो हालत है उस को आप जानते ही हैं । उस का मिलना मुश्किल है । डीजल की मशीनरी भी महंगी पड़ती है । महंगी पर तो आप देने को तैयार हैं लेकिन अगर उसी को बिजली से कोई चलाता है तो आप कहते हैं कि नहीं देंगे । बिजली से अगर बारह सौ या दो हज़ार तक खर्चा आता है तब तो आप छः सौ या एक हज़ार की सबसिडी नहीं देंगे लेकिन अगर डीजल से पांच या छः हज़ार का खर्चा आएगा तो आप तीन हज़ार की सबसिडी दे देंगे । आप जानते ही हैं कि डीजल से पानी निकालना महंगा पड़ता है । इस पर तो आप सबसिडी देंगे लेकिन अगर कोई बिजली से पानी निकालेगा तो आप नहीं देंगे, अधिक अन्न उपजाने के लिए वह बिजली का इस्तेमाल करेगा तो आप नहीं देंगे । मैं समझता हूं कि इस के अन्दर भी कुछ राज की बात है । मैं चाहता हूं कि इस राज का गवर्नमेंट पता लगाये । सम्भव है कि मेरे मन का पाप हो जो मैं कहने जा रहा हूं । चार फरलांग का तीन फरलांग तो कर दिया गया है लेकिन साथ ही यह कह दिया गया है कि सबसिडी नहीं देंगे । ऐसा क्यों किया गया है ? शायद डीजल वाले जो प्राइवेट सैक्टर के आदमी हैं उन से कोई कमिशन बंधा हुआ हो । हो सकता है कि ऐसा हो कि जितने डीजल के इंजन लगे हुए हैं उन पर कोई कमिशन बंधा हुआ हो । डीजल के इंजनों पर किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है । न उन के लगाने पर एतराज है और न कैपेसिटी पर ह । बिजली जितनी प्रोड्यूस होती है सारी पब्लिक सैक्टर में होती है । लेकिन डीजल में यह बात नहीं है । हम ने

इस बिजली के बारे में चीफ मिनिस्टर को अपने यहां लिखा था कि क्यों सबसिडी नहीं दी जाती है ? हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बिजली का इस्तेमाल हो, अधिक से अधिक अन्न उपजे ताकि हमारी जो अन्न की समस्या है वह हल हो । हमारा देश अन्न से हराभरा तभी हो सकता है जबकि सभी सम्भव सुविधायें किसानों को मिलें । सरकार एक तरफ तो कहती है कि लोग अधिक अन्न पैदा करें और दूसरी तरफ जब उससे कहा जाता है कि बिजली दो तो सरकार कहती है कि बिजली नहीं देंगे और अगर देंगे तो सबसिडी नहीं देंगे । ऐसी जब हालत है तो कैसे अन्न की जो समस्या है वह हल हो सकती है ।

मैं चाहता हूं कि आप सारी स्थिति पर विचार करें । यह दो तरफा मार नहीं हो सकती है । अन्न पैदा करने के लिए भी आप कहें और अन्न पैदा करने भी न दें । यह जो पालिसी है इसको आप साफ करें, इसको आप बदलें ।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : सर . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : पांडे जी आप तो बहुत सुन्दर हिन्दी बोलते हैं । हिन्दी में ही बोलिये न ।

श्री काशीनाथ पांडे अच्छी बात है ।

वैसे यह बिल जो सदन के सामने आया है, इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं । हमारे मिश्र जी ने जो अभी कहा है कि थोड़ी सी इस बिल में कमजोरियां हैं । मैं उन कमजोरियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो बात मिश्र जी ने कही है उसमें कुछ भ्रम हो गया है । दरअसल उसी कमी को जो वह कहते हैं पूरा करने के लिए यह बिल यहां लाया गया है । जहां तक प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का सम्बन्ध है यह सही है कि वे वहीं पर अभी कारखाने लगाते हैं जहां पर उनको आशा होती है कि उनको नफा होगा । ऐसी जगहों पर ही वे कारखाने लगाते हैं जहां पर उनको आशा होती है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी बिजली कारखानों या शहरों में ली जाएगी । ऐसी जगहों पर वे नहीं जाते हैं जो जगहें डिवेलप्ड नहीं हैं, जो विकसित नहीं हैं, जो अभी भी बैकवर्ड हैं । अब गवर्नमेंट की जो स्कीम है वह यह है कि एक तरह से सारे देश को, सभी सूबों को वह विकसित करना चाहती है और इसके लिए यह जरूरी है कि बिजली का जो रेट है वह बिल्कुल एक हो और इसी अभिप्राय से यह बिल यहां रखा गया है । चाहे कोई इन्डस्ट्री हो या व्यक्तिगत बिजली का उपभोक्ता हो रेट ऐसा हो ताकि जो अविकसित खण्ड हैं उनको भी लाभ पहुंच सके, वहां पर भी बिजली का उपयोग हो सके । इस दृष्टि से यह जो अमेंडमेंट्स आए हैं इनका मैं स्वागत करता हूं ।

एक दो बातें हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । एक बात अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कही है । उन्होंने मेम्बर जो पार्लियामेंट के हैं या जो असेम्बलियों के हैं उनको बोर्ड पर रखनेके बारे में आपत्ति उठाई है । मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट के या असेम्बलियों के मेम्बर हैं उनमें कांग्रेस के भी मेम्बर शामिल हैं और अपोजीशन के भी शामिल हैं और उन सब के लिए यह कह देना कि ये पापी हैं, इसलिए इनको किसी कमेटी में नहीं रहना चाहिए, यह बड़ी ही गलत धारणा है । इन मेम्बरों में हमारे दांडेकर जैसे भी आदमी हैं जो बहुत काबिल हैं और उनकी काबिलियत पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है । हो सकता है कि उन जैसे मेम्बर को कहीं पर किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए और उनके अनुभव से लाभ उठाया जाए । ऐसी अवस्था में इस तरह का कोई मेम्बरों पर प्रतिबन्ध लगा देना कि ये मेम्बर बोर्ड के नहीं हो सकते हैं और इस तरह की आपत्ति उठाना, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उचित है ? मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से इस तरह की आवाज उठाने का मतलब यह है कि लोग यह समझें कि ये जो पार्लियामेंट के या असेम्बलियों के

[श्री काशीनाथ पांडे]

मेम्बर हैं वे बहुत खराब आदमी हैं और इनको किसी कमेटी में नहीं रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि हम लोगों को तो कम से कम अपनी जबान पर कुछ रेस्ट्रेंट लगाना चाहिये, कुछ रोक लगानी चाहिये। अपनी मर्यादा अपने हाथ में होती है। इस वास्ते हमको अपने बारे में कोई बात कहने से पहले उस पर खूब सोच-विचार कर लेना चाहिये।

अब मैं एम्पलायीज के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें एक विधान ऐसा रखा है कि जो देश में बिजली के महकमे के काम करने वाले मजदूर हैं उनके प्रतिनिधि एडवाइजरी कौंसिल में लिये जायेंगे, उसमें वह उनको स्थान देंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस वक्त गवर्नमेंट रुपया लगा देगी, लाइनें बिछा देगी और उसके बाद जगह-जगह ट्रांसमिशन स्टेशन लगा देगी, बड़े-बड़े बांधों से बिजली पैदा कर देगी, सब कुछ कर देगी तो वहां पर उस के बाद सिर्फ दो पार्टीज रह जायेंगी, एक मजदूर और दूसरी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट और मजदूरों में सहयोग न हुआ तो इसका नतीजा देश की बरबादी के रूप में हमारे सामने आएगा। आज जो बिजली पैदा हो रही है उससे न केवल प्रकाश मिलता है बल्कि तमाम इन्डस्ट्री भी चलती है। उससे पानी निकलता है और उसी से सिंचाई होती है। ऐसी अवस्था में अगर मजदूर असन्तुष्ट रहेंगे तो आप इस सब काम को नहीं चला सकेंगे। इस वास्ते बजाय इनके मजदूरों के प्रतिनियधियों को कंसलटेटिव कमेटी में रखने के क्यों नहीं आप बोर्ड में रखते। बोर्ड में उनके रहने से आपकी मैजोरिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक आदमी इनका लाभदायक हो सकता है। मैं समझता हूं कि बोर्ड में बहुत से फैसले होंगे जिनमें इनकी सलाह हो सकती हैं। इनके वेज के सम्बन्ध में सवाल वहां आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी बात हुई है। बोर्ड में उनके प्रतिनिधि रहने से हमारा खयाल है कि आपको फायदा ही होगा।

शैड्यूल छः में कुछ इस तरह का संशोधन हुआ है जिसमें कहा गया है कि मजदूरों का जो प्राविडेंट फंड है या ग्रेचुटी है या पेंशन है इनकी रकमें रेवेन्यू से काट कर जमा हो सकती हैं। केवल यह कह देना कि काटा जा सकता है, इस तरह से इसको मेंशन कर देना काफी नहीं है। इससे काम नहीं चलता है। जिस स्कीम पर करोड़ों का काम होता है वहां पर ऐसा होता है कि मजदूर लाइन पर काम करता है और लाइन ज्यादातर ए० सी० लाइन होती है और उसमें जरा सी भी असावधानी हो जाती है तो मजदूर मर जाता है। उसके बाद उसके परिवार वालों को कम्पेसेशन मिलता है। लेकिन उससे उसके बच्चों का कुछ नहीं बनता है, न उनकी पढ़ाई हो पाती है और न कुछ और इंतजाम हो पाता है। और इस तरह से पेंशन की बात पर इस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिये। पेंशन के बारे में कोई इन्तजाम ऐसा हो जाय ताकि जो फिक्स हो जाए वह पेंशन उसको मिले या उसके परिवार वालों को मिले। केवल यह कह देने से कि पेंशन के लिए रुपया मिल सकता है, काफी नहीं है।

एक चीज इसमें और कही गई है। जिस समय कोई अंडरटेकिंग प्राइवेट हाथों से गवर्नमेंट ले ले तो वे सब चीजें प्राइस में शामिल होंगी। इस आधार पर यह कहा गया है कि लेबर के जो ड्यूज हैं, मजदूरों के जो ड्यूज हैं वे प्राइस देते वक्त काट दिये जाएं, इस में जो डिफिकल्टी पैदा होती है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मैंने इसको देखा है तथा दूसरे सूबों में यह डिफिकल्टी पैदा हुई है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड अब ज्यादा से ज्यादा अंडरटेकिंग्ज को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसमें होता यह है कि ज्योंही वह किसी प्राइवेट कम्पनी को लेते हैं तो मजदूरों

को कह दिया जाता है कि तुम्हारी सर्विस बिल्कुल नई है । अब आप सोचिये कि जो मजदूर उसमें बीस साल से काम कर रहा है जब वह आपके पास आता है तो उसकी सर्विस नई होगी और दो महीने के बाद वह मर गया तो गवर्नमेंट के पास आने का मतलब यह हुआ कि यह उसके लिए एक अभिशाप सिद्ध हुआ । मेरा मतलब यह है कि आप उसको कहिये कि जब अंडरटेकिंग्स को आप लेंगे तो उसकी सर्विस कंडीशंज में कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी । अगर गड़बड़ी होती है तो सिवाय डिसटरबेंस के और कुछ नहीं होगा ।

ड्यूज का जहां तक सवाल है लॉ के अन्दर कुछ चीज रहती है, कुछ प्रावधान रहता है । लेकिन जब कोई पर्टिकुलर इशू आता है तो कोर्ट उसे डिसाइड करती है । हैंड्ज जब चेंज होते हैं और कोर्ट से यह डिसाइड नहीं हुआ है कि ड्यूज पाने का मजदूर को हक है या नहीं है । ऐसी हालत में परचेज करने वाला इसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वह रुपया वसूल कर ले । तब कौन दिलायेगा रुपया ? इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि आप स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट को अधिकार दें कि वह जिम्मेदारी फिक्स कर दे, लेबर के ड्यूज बता दे ताकि उनको दाम में से काटा जा सके और अगर दाम में से नहीं काटे जाते हैं तो खरीदने वाले से वसूल किये जायें । अगर ऐसा होगा तो बात खत्म हो जाएगी और सारी चीज सोफ हो जाएगी और आगे कोई डिसप्यूट पैदा नहीं होगा । इस वास्ते इसकी और भी आपकी चाहिये कि आप ध्यान दें । अगर आपने इन सब बातों की ओर ध्यान दिया तो आगे चल कर जो अंडरटेकिंग्ज आप लेने वाले हैं उनमें कोई किसी प्रकार के झगड़े पदा नहीं होंगे ।

Shri Warior: I would have welcomed the Bill, but looking into it more closely I was very much disappointed. Along with tightening of the control of the Central Government over the private licence, I think the Central Government should have taken this opportunity to tighten control over the State Electricity Boards also. That was my anticipation, but Government lost a golden opportunity to do that.

Actually now the major spending and investment is done by the Central Government. I know of instances—I had put very many questions on the State Electricity Board of Kerala in this House itself—where the entire funds are allotted by the Central Government and they are used by the State Electricity Board in such a way that it is not above suspicion. I am mincing words here, I am minimising my opinion, this is the mildest way of putting it. Not only that. This has become now almost a collusion between those in authority and those who benefit as contractors.

Rajaji said that India has become already a contractors' paradise. Though I cannot subscribe to it completely, cent per cent, still there is much sense in it, and if there is any sense in that, it is much more in the electricity department than in any other department.

For one thing, most of our projects are in the hill areas unknown to civilised portions of the land. It is in the high forest and nothing could be done. Even the labourers can be shot down like hogs or pigs, and there is nobody to question. What is actually going on there nobody knows. There had been so much trouble not only for the people at large, but also for the Government. These are things I am saying not in a general way; I have got enough of instances in my mind as a background from which I am saying all this.

What happened recently in the Idiki project in Kerala is well known

[Shri Warior]

to all. The entire forest area was cordoned off by the police, and the Government sat tight without coming to the conciliation of the dispute between the contractor management and the workers.

Now, a contract was given to somebody—I have no belief in any contractor—and other contractors naturally got vexed about that with the electricity board and they also kicked up a row. Not only that. They sued the Government in the High Court for a writ. That stands there. But now the reason given for this change is that the new beneficiary is more substantial and could execute the work. He has more funds for that. But as soon as the contract was given, which is a centrally sponsored scheme, crores of rupees were handed over to this contractor, without even executing a single item of the contract. If he is so financially substantial, what prompted the electricity board to lend him before scrutinising whether he has executed anything or not. Is it the custom of the Government that as soon as a contract is entered into with a contractor, huge sums are disposed of like that? They do not care because the Central Government is giving the money. These are fishy things, these are things not above suspicion. I can quote innumerable instances like that.

There is another instance also. The contract will not stipulate all the minor items in the contract. The major item only is stipulated, and when the major item is executed, these minor items are added now and then, and for that there is no tender at all, there is no rate quoted. Whatever the contractor says and whatever the electricity board consents to is the rate and whatever loss he has incurred in the competitive tenders for the major portion of the work be compensated by these minor agreements. These are the main practices. I can quote innumerable other things, but these are the main practices.

Now, look at this picture. Hundreds and thousands of families are ejected from the project areas. Nobody cares for them. If we ask the Central Government about that, the Central Government shirks and shifts the entire responsibility to the State Government. If we ask the State Government they say it is a centrally sponsored scheme, they have nothing to do with it. And these people are shuttled up and down without proper rehabilitation, without proper compensation, and without even human consideration, camping them somewhere not inhabitable. We had a hell of a lot of trouble because of this. Even now it is so. I will not go into details. So, I was thinking that now the Central Government would take the opportunity to make more effective its control over the State electricity boards, which are not like autonomous bodies of previous times, but more or less dependent upon the Central Government; and this is the time, this is the reason and this is the justification also for the Central Government to have more control over them. I request the Minister to give us this information according to his knowledge because personally he knows everything in his department, I am quite sure about it, because he was the most prominent executive of the Central Water and Power Commission, and now he is Minister as well. I had also very many opportunities of travelling along with him as Member of the Public Accounts Committee and Estimates Committee and see most of these projects, and I know it had gone inside his mind, but now I do not know what transformation has taken place in him.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): He is a Minister.

Shri Warior: As a Minister there must be some change. I will ask him how many state boards are functioning satisfactorily according to him, which are the States which are so lucky and fortunate in that respect. I

am quite sure he will reply that out of the 16 States, not more than three or four at the most are functioning properly and in an efficient manner. What about the rest?. Are we going to spend the money of the Central Government, the people's money, and entrust it to these people to squander it like anything, or are we going now to take powers in our hands so that this inefficiency and corrupt administration in the electricity department will come to an end? That is the main question. The Augean stables must be cleaned and for that very strong action is required from the Government.

15 hrs.

The second point I want to make is —I will come to the Bill—this: in the whole supply of electricity, what is the direction, what is the orientation? Whenever there is an economic, social or political crisis in this country, everybody will turn to only one man, the farmer, the villager, but whenever any action is taken, that will go diametrically opposed to that direction, to the detriment of the villager. Here in India, political or economic or social evolution or revolution must take place from the village, but the most neglected people are the villagers, the agriculturists. I know the reason for that. The reason is that the villager has nowhere to go, and those people in authority who are fortunate enough to direct the destinies of this country are quite sure that they will not go anywhere, they will stick to the land, they will plough the land, loss or profit. They will die there, mute and slavish and cursing only their fate. Go to any village and ask any villager: why are you so poor, so destitute after working so hard? I was amazed to see in so many villages of Rajasthan villagers working in the hot blazing sun from so early in the morning that they can barely see the hair on their toes to such time in the evening when they can barely see their hair on their toes, 12 or even 14 hours. They never unleash the bullocks and go on ploughing and sowing. After all this inhuman labour, what do they get? Nobody cares to know. What do they realise in the market? That is the state of affairs with regard to electricity also. All others get electric power, industries, palaces, towns, everybody gets it except the villager. We depend upon the villager for our socio-economic and political or whatever improvement and advancement. The Government is even now not prepared to reorient its policy. You look at Bombay or any city. There are neon lights, flourescent lights or any kind of light. You are wasting electricity. Still the poor villager will not have it. These things must go once and for all. Then only we can have any hope of progress for our country.

There are certain funny provisions in this Bill. About the MLAs and MPs, why should the Government be so anxious . If the MLAs and MPs should be compensated after they go away from the House, let them be given five or ten acres whichever is an economic holding and let them cultivate it. Why should these posts be reserved for them? When I read this, I begin to think of it now; I did not think of it till that time; I now ask myself: how can I also get into the Board?

Shri Umanath (Pudukkottai): You cannot, unless you go there.

Shri Warior: I will go to the other side; that is the way. That is the hook. That is how people are taken. Most of these people are very honest people but they are hooked. I do not want that. Why these considerations and qualifications for the legislators? Why not have some disqualification for the engineers and retired servants of the Government? Especially retired engineers of the electricity department are taken by the same contractors who had dealings with them. Will the Minister bring forward a rule that no engi-

[Shri Warior]

neer of the electricity department can accept employment with such contractors until after the expiry of six years from their retirement date. You see this type of collusion. I will support a measure which will exclude those who are in high authority and who can sanction funds and who can accept tenders from accepting employment for six years after their retirement in those areas, in the neighbouring areas where they were employed.

Mr. Dandeker has to take care of the interest rates on investments made prior to 1965 and after 1965. I do not go into that. There can be justification; there can be no justification.

About the tenders there are certain changes made for Rs. 25 lakhs. Is Rs. 25 lakhs a paltry amount? In our country no single paisa is a paltry amount. We have to guard against it. There might be delay. I am not for inordinate delay in the execution of projects. This may cause some delay. But at the same time there are safeguards also.

Dr. K. L. Rao: What I want to point out here is that it is publication of the simple description of the scheme; that has nothing to do with the acceptance of the tender.

Shri Warior: That is all right. I will give an instance. According to the technical advice of the commission a particular scheme is put forward. People also have a say in it when they get to know that. At times we may give an opinion which may be against a scheme on certain other grounds other than the technical grounds. Suppose there is a scheme and for executing it thousands of people were to be ejected from that area. We will prefer not to eject people and let the scheme go. Technically the Ministry cannot do that; it can be technically feasible, possible, in the long run advantageous. But immediately there may be issues affecting the people and in such matters the people's voice must be heard. I think the former provision was much better in that respect. I will leave other things to others. In conclusion I may say that a Bill which will contain all the necessary demands of the time must come.

Shri Muthiah (Tirunelveli): Mr. Deputy-Speaker, I like to speak a few words by way of introduction on the generation and supply of electric power in our country before I come to the Bill proper. Electric power is most essential for our economic development, both agricultural and industrial. Lenin laid the greatest stress on power development for the economic progress of Russia. Agriculture depends in a large measure upon power development and power supply. Power generation today is inadequate to meet the growing demands of our country. According to the Third Annual Electric Power Survey of India published by government, the installed capacity in 1966-67 is 12951 MWs and the target fixed for the Fourth Plan is 24000 MW. For more electric power should be supplied to agriculture than is done today. Today, industry consumes about 70 per cent of power supply and agriculture consumes less than 10 per cent of the total supply. The charges for agriculture should be cheap; not more than nine paise per unit as in Madras State. There should be no minimum charges for consumption for agricultural purposes. In power supply, both for agriculture and industry, Madras State is leading, but in power generation, Madras State is very deficient. Madras State depends mostly on hydel projects for electric power supply for its numerous industries, both big and small and for its agricultural needs. The rains often fail and the hydel projects consequently fail to

meet the demand. Severe cuts are imposed on the consumers in summer every year. The thermal power in Madras is not sufficient to supplement the hydel power. The thermal power produced by Neyveli and Ennore plants is not enough to meet the acute shortage. Therefore, I plead with all the earnestness that I can command and in all sincerity before the hon. Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power, Dr. K. L. Rao, that the proposed thermal plant at Tuticorin is quite necessary for the southern districts of the State; it should be set up at Tuticorin without delay during the Fourth Plan period.

Now, I come to the Bill. The object of the Bill is to remove certain difficulties encountered in the working of the Electricity (Supply) Act, 1948 and to effect necessary changes in the Act for raising capital for power development. An important change effected is the raising of the amount of reasonable return for the license from 15 per cent to 20 per cent. The second change is a provision to empower the licensee to levy minimum charges from consumers, especially the industrial consumers. The third important change effected in the Bill is the provision to permit the appointment of Members of Parliament and State legislature to the Boards immediately after they cease to be such Members and not one year after, as in the old Act. This, I submit, is a desirable change, though some Members sitting in the Opposition may not quite agree. The new Bill provides for the levy of different rates in the States, though the general policy is for the adoption of uniform rates throughout the State for each class of service.

Now, I come to the clauses of the Bill. Clauses 20, 21 and 22 of the Bill have retrospective effect, while the rest come into force on the day when the Bill becomes an Act. I feel that it will be better to do away with the retrospective provisions and to have uniformity. Section 29 of the old Act is replaced by a new clause. According to the new clause, every scheme sanctioned shall be published in the Official Gazette excepting schemes costing less than Rs. 25 lakhs. Before sanctioning any scheme costing more than Rs. 1 crore, the Board shall consult the State Government and the Central Authority and go ahead with the scheme after their approval. This is a good check on the Board.

Section 49 is replaced by a new clause. According to the new clause, the Board may supply electricity to any person other than a licensee upon proper terms and conditions. The Board has the power to fix different rates for the supply of electricity, to any person other than a licensee.

After section 60, a new clause 60A has been inserted in the Bill. According to this new clause, the period of limitation is extended beyond three years to the Board for the recovery of arrears due in connection with the consumption of electricity. The amendment of section 67 of the parent Act provides for a general reserve fund with a ceiling of 15 per cent of the fixed assets, seven per cent mor than the ceiling allowed in the old Act, and for the creation of a new fund called the Development Fund, meant for development of electricity in the State.

Section 68 is replaced by a new clause in the Bill. This clause provides for a depreciation reserve. An amendment of the Fifth Schedule of the parent Act provides for the rate of interest to be two per cent more than the Reserve Bank rate. The amendment to the Sixth Schedule authorises a licensee to levy, with the previous permission of the State Government, minimum charges for the supply of electricity for any purpose, domestic, industrial or agricultural. The amendment provides that the expenditure items of the Board shall cover contributions to provident fund, staff pension, gratuity, expenses

[Shri Muthiah]

on apprentice and other training schemes and interest on loans.

With these words, I support the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Umanath.

Shri A. S. Saigal (Janjgir): Nobody has spoken on behalf of Madhya Pradesh. I request you to give me a chance.

Shri Umanath: Mr. Deputy-Speaker Sir, I do accept the position that with a view to facilitate the speedy extension of electricity in our country, the 1948 Act requires certain important revisions. Apart from its domestic use, electricity is a strategic element for the accelerated development of our industry as well as agriculture. Hence a revision should be made, and according to me, it should be directed against certain provisions that hamper the speedy extension of electricity in these key sectors. I say speedy extension because extension is already taking place, and so I am laying emphasis on the question of speedy extension, or adequate extension, according to the country's developmental needs.

To ensure such a speedy extension, two things are important. One is the question of electricity rates. As far as domestic consumption as well as agriculture is concerned, especially agriculture, the rates will have to be reduced. Secondly, there is the question of percentage return. If a scheme for extension of electricity is to be approved, the calculation is made whether capital expenditure gets back a percentage of return. For example, in Madras State, it is calculated as 10 per cent. Now, in that percentage return also—there must be a reduction. Unless these two things, namely, reduction in the rates and percentage return, are not made, to talk of acceleration would be a meaningless phrase. To bring about such a reduction in these two items, I feel that electricity undertakings must be converted into really public utility service institutions. I say that because today they are not. Today they are primarily profiteering industries. In the beginning, it was a different position. Today, the electricity industry or the power industry has taken up a position where it has become one of the first-rate profiteering industries. Unless this position is changed, a reduction in the rates and the percentage returns will not take place.

I will give you a few examples of profitability. I shall be giving you certain figures from the balance-sheets of leading concerns. In Andhra Valley, for example, the gross profit as percentage of total capital emp'oyed in 1963-64 was 10.3 per cent; sufficiently high. In 1964-65, it was 10.5 per cent. In Ahmedabad Electric, in 1963-64, it was 8.7 per cent; in 1964-65, it was 12.4 per cent. In Tata Power,—it is an important institution —in 1963-64, it was 11.3 per cent, and in 1964-65, it rose to 20.9 per cent. That is the huge profit they get. I can understand the vehemence of Shri Dandeker, my colleague here, when he talked about sub-section 10. Tata Power, wthin one year, gets from 11.3 per cent to 20.9 per cent.

If you take the assets of Tata Power, in 1963-64, it was Rs. 26.1 crores and within one year, in 1964-65, it rose to Rs. 28.6 crores. In one year, the assets increased by about 2.5 crores of rupees. I will give you another aspect of the profitability of this industry. There is a calculation showing the value added as percentage value of output. This is made by the Annual Survey of Industries by the Central Statistical Organisation for the year 1963. In textiles, the most organised industry, this percentage is 29.7. Tobacco, 24 per cent; iron and steel, 26 per cent; basic industries, chemicals and fertilisers, 28 per cent. Electric light, power and gas manufacture and distribution are

taken together. The most important element in that group is power. In power, this percentage is 35. So, if you take the value added as percentage value of output, as compared to other industries, you find that the highest percentage, that is, 25 per cent, is in power production.

There is another calculation—value added per worker in the industry. This figure is Rs. 2986 in textiles, Rs. 6002 in tobacco, Rs. 3904 in iron and steel and Rs. 4649 in the power idustry. As compared with the most organised industries like iron and steel and consumer industries like textiles, the power industry, which is mainly meant to be a public utility service, is occupying the position of a first rate profiteering industry in the country. Profitability and service to the public cannot go together. Either the Government should take up the position that this profitability will be defended and further increased at the cost of the consumers and the public or, if they want to serve primarily the interests of the consumers, of the public, of agricultural development, they will have to come down with a heavy hand on this profitability.

We must trace the springs sources of this profitability. For that, we need not go anywhere else. Certain provisions of the 1948 Act are the springs and sources. The standard rate provided therein is calculated on the Reserve Bank rate plus an additional percentage. Unless this formula is fundamentally changed, unless there is a delinking with the Reserve Bank rate and a new formula is introduced for the purpose of accelerated agricultural and other development, unless there is an amendment of the 1948 Act to this effect, no development can take place. Does this Bill contain such an amendment? No. It retains the profit springs formula and it even justifies it. The Statement of Objects and Reasons says:

> "If the Bank rate increases, it is justifiable to allow the licensees to earn reasonable return based on increased Bank rate."

So, where exactly you must keep your finger, there it is not kept. On the other hand, it is defended. A distinction is made between past investments and new investments. Even the flat rate of 7 per cent on past investments is based on this linking formula, i.e. bank rate plus something extra. So, for the purpose of accelerated development of agriculture and other developmental activities and for serving the public and the consumers, the first thing to be done is that this provision must be changed.

Instead of doing this, Government have come forward with a small change, which is not materially coming to the rescue of the consumers. This small change might be helpful for the ruling party for the 1967 General Elections and they might say, "Look here, for the entire block they were getting so much. Now we have divided it," and so on. This small change may help the ruling party to say that they are doing these things to achieve a socialistic pattern—they do not want a socialist pattern—and so, this political purpose may be served, but it does not touch the fringe of the problem.

While I agree that uniformity of rates must be attempted, which the Bill seeks to do as per the Minister's statement, markedly backward areas in each State with regard to power supply and extension must be treated on a different footing. That is an important point which must be taken care of by the Minister. Pudukottai, from where I come, which was an erstwhile native State, is a backward area. The agriculturists there depend on rains and nothing else. They have no perennial source of water. Day in and day out the Ministers, both at the State and Central level, are telling the people—Mr. Subramaniam used to say, I remember—"I do not care about the expenditure. I will supply all the money, power and everything; I want production of foodgrains." In Tirumayam taluk of Pudukottai, the villagers of Sadayampatti believed the minister's statement and put in 104 applications for pump set electricity con-

[Shri Umanath]

nections for irrigation. All the deposits necessary under the Act were made. It is three years now and still they have not got the connection. Not a month or two, but three years have passed. This is just one example. Recently for 15 days I toured my constituency on cycle and I found this is the position in villages. When I ask the engineers, they say, "We must get 10 per cent return on any scheme. If the Sadayampatti scheme is approved, it will give only 7½ per cent return. So, we have not approved it." If all the 104 applications are approved and connections are given, imagine what will be the agricultural production in that backward area. Yet, because of a difference of 2½ per cent, that production has been stopped. This is the Government's policy.

The Planning Commission team visited the eastern districts of UP for investigating how to accelerate development in backward areas. They have made certain recommendations for backward pockets in all the States. One recommendation is in those backward areas, heavy investments must be made in power, communications and such other things, without caring for return on a surplus basis. It means, if 104 applications come, you must sanction more and be liberal. But even for ordinary extension, the percentage of return comes in the way. How can this be done on a surplus basis? The District Development Council of Tiruchi District, during their last month's meeting, have unanimously recommended that this percentage of return condition in backward pockets must be abolished and they must be given exemption. So, the Act requires revision in this direction also, but it is not being done.

What is the state of affairs in the Chandannagar licensee area, which is a suburb of Calcutta, just a few furlongs away from Calcutta? Whereas the Calcutta State Electricity Board is charging 3 annas per unit, the rate in Chandannagar, just a few furlongs away, is 5 annas per unit. There is a difference of 2 annas per unit just for storing and distribution. If this sort of thing goes on, naturally discontent will be most. Notwithstanding this profiteering, no extension work is undertaken there worth the name. Moreover, provident fund accounts have not been submitted to the P.F. Commissioner by this private licensee notwithstanding repeated requests. It has created a sort of insecurity in the minds of the workers.

Now, for the hon. Minister's attention, I would like to submit that his lease is going to be over by 1967. This is the best time for the hon. Minister to intervene and see that the lease is not renewed and the Government takes over that particular area which requires a lot of development.

With these few points, Sir, I would like to request the hon. Minister to seriously consider them and give his reply.

श्री न० प्र० यादव : डिप्टी स्पीकर साहब, घंटों की प्रतीक्षा के बाद आपकी दृष्टि इधर हुई, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आप के माध्यम से अपने विद्युत राज्य मंत्री डाक्टर के० एल० राव को भी धन्यवाद देता हूं। जो संशोधन बिल विद्युत मंत्रालय की ओर से लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं डाक्टर राव का ध्यान उत्तरी बिहार की ओर ले जाना चाहता हूं। दो वर्ष पूर्ण डाक्टर राव, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र, उस में करीब दिन भर घूमते रहे। उसके पश्चात् रात को करीब 20 मील तक भ्रमण करने के बाद इन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि 20 मील की दूरी तय करने के बाद भी कोई बिजली का एक भी बल्ब दिखाई नहीं पड़ा। इन्होने खुद महसूस किया था कि यह एरिया बिलकुल पिछड़ा हुआ है, इस एरिया में जितनी जल्दी हो सके बिजली का प्रबन्ध मैं करूंगा। लेकिन दो वर्ष

बोल जाने के पश्चात् भी जो स्थिति उस इलाके की दो वर्ष पूर्व थी आज भी वही स्थिति सीतामढ़ी की है । इसलिए मैं डाक्टर के० एल० राव का ध्यान पुनः उत्तरी बिहार की ओर ले जाना चाहता हूं । उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बिजली के रेट में बहुत अन्तर है । दक्षिणी बिहार वाले को सस्ती बिजली मिलती है । लेकिन उत्तरी बिहार जिसकी आबादी 1 करोड़ की है, वहां के किसानों को बिजली बड़े महंगे रेट पर मिलती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से डाक्टर राव का ध्यान उत्तरी बिहार की ओर पुनः ले जाना चाहता हूं । उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बिजली के रेट में अन्तर नहीं होना चाहिए । उत्तरी बिहार में अभी तक जितने कुएं बनाये गए हैं 15 वर्ष के बीच अभी उनमें 5 पर सेट कुएं भी ऐसे नहीं हैं जहां बिजली की लाइन गई हो । मेरे जिले में हाजीपुर इलाका है, जहां कुएं में पांच हार्स पावर के भी मोटर लगें हैं और एक कुएं से करीब दस एकड़ जमीन की सिंचाई होती है । लेकिन इस बार मैंने देखा कि जहां वह कुएं के मोटर लगे हुए हैं वहां बिजली की लाइन कभी दिन में दो घंटे कभी चार घंटे मिलती थी जिसकी वजह से हाजीपुर इलाके के किसानों का जो प्याज और केले की खेती करते थे, उन बेचारों का सारा परिश्रम बरबाद हो गया । केला, प्याज वगैरह जो फसल वह अपने खतों में लगाए थे, वह सब सूख गई । इसलिए मैं डाक्टर राव का ध्यान उत्तरी बिहार की ओर ले जाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जहां भी जिस कुएं में बिजली की लाइन गई है, खेती के समय उन्हें कम से कम दिन रात 24 घंटे बिजली की लाइन मिलनी चाहिए जिससे किसानों के जो लहलहाते हुए पौधे इस साल मई और जून के महीने में सूख गए, वैसे फिर सूखने न पावें । इस साल खेती पर जो किसान काफी खर्च किए हुए थे, उनको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला । वहां के किसान इस बार बरबाद हो गए । वहां बहुत बड़ी तबाही आ गई ।

अभी हमारे देश में करीब 214 ऐसी प्राइवेट बिजली की कम्पनियां हैं जिन के द्वारा हमारे भारतवर्ष के बहुत से भागों में बिजली सप्लाई होती है । उत्तरी बिहार के दरभंगा, लहरिया सराय और मुजफ्फरपुर जिले में भी प्राइवेट कम्पनियों की ओर से बिजली की सप्लाई होती है । उन को बिजली तो बरौनी से मिलती है । सिर्फ उनके पोल और तार लगे हुए हैं और उनका कोई खास किसी चीज पर खर्च नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि 214 जो प्राइवेट कम्पनियां देश में हैं, शीघ्रातिशीघ्र उन कम्पनियों को सरकार को ले लेना चाहिए, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ।

श्रीमन्, मैं देखता हूं कि सीतामढ़ी में, मोतीहारी में, जहां एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिहार की ओर से बिजली दी जाती है उन्हें सस्ती बिजली मिलती है । लेकिन मुजफ्फरपुर शहर, जिस की आबादी करीब १ लाख है, दरभंगा, और लहरिया सराय जहां प्राइवेट कम्पनियों की ओर से बिजली देने की व्यवस्था है वहां रेट में काफी फर्क है । इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनको सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और रेट में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर शहर में रात में कभी दो घंटे, कभी 3 घंटे बिजली की लाइन बन्द हो जाती है जिससे वहां के रहने वालों को काफी दिक्कत होती है । जितनी जल्दी हो सके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, लहरिया सराय में जो बिजली देने की व्यवस्था है, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिहार के हाथ में आ जानी चाहिए । वहां की व्यवस्था बहुत खराब है ।

[श्री न० प्र० यादव]

श्रीमन, मुझे दो हफ्तें पहले मद्रास स्टेट में जाने का मौका मिला । वहां मैंने देखा बिजली से काफी जमीन की सिंचाई होती है । और मैंने देखा कि 20–25 फीट गहराई में जाने पर ट्यूब बेल से किसान को पानी मिलता है और एक जिले में मैं गया था वहां करीब दो हजार ट्यूबवेल लगे हुए हैं और एक एक गांव में दस दस बारह बारह ट्यूबवेल लगे हुए थे और हरएक कुएं में बिजली की लाइन थी । वहां किसान काफी खुशहाल है । बिजली की लाइन गयी है जिससे उनकी जमीन की सिंचाई होती है । उत्तर बिहार सभी मानों में अभी तक पिछड़ा हुआ है । न वहां सड़क बनी न बिजली की लाइन गयी । इसलिए उनका ध्यान इस ओर जाना चाहिए ।

एक वहां बागमती नदी है । स में हमेशा पानी रहा करता है । बागमती नदी के किनारे दोनों तरफ बिजली की लाइन दे दी जाय तो उससे हजारों गांवों के किसानों को फायदा होगा । बागमती, अधवारा, रातों, लखनदेई नदियों के किनारे जो गांव बसते हैं यदि उनमें रहने वाले किसानों को बिजली शीघ्रातिशीघ्र दी जायगी तो मैं श्रीमन, आप को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तरी बिहार में खास कर के मुजफ्फरपुर, मोतीहारी, और दरभंगा के किसानों को काफी फायदा होगा और जो हम अभी गेहूं वगैरह विदेशों से लेते हैं यदि बिजली की लाइन बागमती, अधवारा, रातों, लखनदेई नदियों के दोनों किनारों के गांवों के किसान को मिल जायगी तो वहां काफी अन्न पैदा होगा और उत्तरी बिहार में कभी विदेशों से गेहूं चावल लाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

इसलिए मैं श्रीमन, पुनः डाक्टर राव का ध्यान मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी की ओर ले जाना चाहता हूं । श्रीमान, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

Shri Kashi Ram Gupta: Mr. Deputy-Speaker, Sir, before I proceed to speak on the Bill I have to point out something to the press. On days on which both Shri Kashi Nath Pandey and myself speak, sometimes our names are confused and also our party affiliations and we are both put to trouble. Once I was named as Congressman and the people of my area questioned me like anything. I am pointing out this today because both of us have spoken today.

Coming to the merits of the Bill, I think a veteran like Dr. Rao should have waited for some time instead of bringing it forward now, because the existing Act will require far-reaching changes because of the grid system and extension of rural electrification. So, he could have waited for some more time and brought a more comprehensive Bill.

For example, in Chapter III, clause (6) of the 1948 Act there is provision about the working of two Inter-State Boards. Now the time has come when there will be more than two Boards working together and there is no provision in the Act to cover that. Therefore, this clause as well as similar clauses will have to be amended to cover the new situation.

When we take up rural electrification, the borders of States will create practical difficulties. I am saying this from my own personal experience. For instance, Alwar in Rajasthan was to get electricity from the neighbouring Punjab and the target fixed was 1,700 kw from Taoru sub-station. Unfortunately, we have been able to get only 400 kw. There is such a big gap between promise and supply and we are helpless because the Act does not contain any provision to compel one

State to supply electricity to another State if it does not comply with the request. Therefore, provision will have to be made in the Act to cover such contingencies.

It is the common experience in the country, particularly in Punjab, Rajasthan and Madhya Pradesh that the failure of the hydro-electric power stations upset the economy of the State Electricity Boards. On the one hand, we say that the Electricity Boards should be autonomous and that they should work like commercial concerns. But the Government act in such a way that affect the working of the Electricity Boards, they feel helpless and face the consequences and as a result the people, the agriculturists and the industries are suffering. It is for the Minister to see that such things do not happen.

Shri Umanath wanted the State Electricity Boards to work as public utility departments. I am sure that he is not unaware of the working of Government departments, where there is complete chaos. Surely, that is not what we want. Therefore, in my opinion, while Government should subsidise schemes of rural electrification and so on and so forth, the Electricity Boards should be run like other business concerns, allowing for income-tax, bonus etc.

Coming to the clauses of the Bill, I have something to say on clauses 11, 12, 13 and 14. In clause 11(4) it is stated:

> "In fixing the tariff and terms and conditions for the supply of electricity, the Board shall not show undue preference to any person."

I do understand the object of having such a provision because no Board is expected to show such preference. This Government also knows that if any preference is shown it is for political reasons. It is given only when politicians interfere. Therefore, instead of having such a provision in this enactment, they should better set their house in order. These words are useless here and convey no meaning.

In clause 13 the limits of "twentyfive thousand" and "seventyfive thousand" have been raised to "one lakh" and "three lakhs" respectively. No reasons have been given for this increase. I hope the Minister will give them in the course of his reply.

In clause 14 it is expressly written:

> "the balance to be appropriated to a fund to be called the Development Fund to be utilised for—
>
> (a) purposes beneficial, in the opinion of the Board, to electrical development in the State;
>
> (b) repayment of loans advanced to the Board under section 64 and required to be repaid:
>
> Provided that where no such loan is outstanding, one-half of the balance aforesaid shall be credited to the Consolidated Fund of the State."

It is not clearly mentioned as to whether this will be the order of priority or not. Unless that is clearly mentioned, practical difficulties will come in. Therefore, I suggest that it should be very clearly mentioned that the first priority will be given to electricity development in the State, next to repayment of loans and so on.

When we are going to have an all-India grid, naturally the services should be treated uniformly. Now different Electricity Boards have different grades for their employees because of which there is labour trouble everywhere. If we have an all-India grade for the employees of the various State Electricity Boards with uniform rules of promotion the labour trouble can be avoided. It will also result in increase in efficiency.

Coming to the present functioning of the Electricity Boards, I must very frankly say that for the last ten years,

[Shri Kashi Ram Gupta]

specially in Rajasthan, there is a lot of corruption, nepotism and favouritism. Whenever the poor kisan or cultivator goes for a connection, he is made to pay Rs. 100 or more as bribe to the officials. Government should take steps to put a stop to this. If they bring in the argument that it is the responsibility of the States, I do not agree. I say that it should be provided for in this very enactment especially when an all-India grid is going to come into existence.

Lastly, so far as the agriculturists are concerned, there is a demand from the whole House that the rate should be uniform and that it should be subsidised by the Government. Amendments have been moved to this effect. I hope the hon. Minister will accept those amendments.

श्री बृजवासी लाल (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

यह जो इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एमेंडमेंट बिल आया है इस में जो त्रुटियां हैं उन में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मुझे तो सिर्फ चंद बातें उत्तर प्रदेश के बारे में अर्ज करनी हैं।

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई के सिलसिले में कुछ ऐसी अड़चनें रख छोड़ी हैं कि जिन से वहां के काश्तकारान को खास तौर से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे सिंहासन सिंह जी ने कहा है कि नहर और ट्यूबवेल जहां हैं वहां चार फरलांग के अन्दर बिजली नहीं दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि एक मिनिमम चार्ज उन्होंने रख छोड़ा है जो कि साठ रुपये से नब्बे रुपये तक पर हार्स-पावर है। जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है मैं बता सकता हूं कि वहां पर छोटे छोटे काश्तकार ही अधिक हैं। वहां चकबन्दी हो रही है और लोगों के चक इकटठा हो रहे हैं। लोग कुएं बना रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास चार से पांच एकड़ की जोत है। उन में वे लोग अपने कुएं बना रहे हैं और चाहते हैं कि उनको उन कुओं के लिए बिजली मिल जाए। लाइन उधर जाती है लेकिन फिर भी उनको बिजली नहीं मिल पाती है। एक बात यह भी है कि जब उनको मालूम होता है कि साठ रुपये और नब्बे रुपये मिनिमम चार्ज उनको देना पड़ेगा तो जिन के पास चार या पांच एकड़ ज़मीन है वे इतना पैसा नहीं दे सकते हैं और इसलिए अगर उनको बिजली दी भी जाती है तो वे लेने से इन्कार कर देते हैं। दूसरी एक बात यह भी है कि अगर कहीं ट्यूबवेल का एरिया हुआ या नहर पास हो रही है तो उनको बिजली नहीं मिलती है। ये कुछ अड़चनें और मुश्किलात उनके सामने हैं जिन को दूर करना बहुत आवश्यक है। जब तक इनको दूर नहीं किया जाएगा तब तक किसानों को आसानी से पानी नहीं मिल पाएगा।

आप खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं और इस पर बहुत जोर भी देते हैं। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार कर क्या रही है इसको भी देखा जाना चाहिये। जहां तक मिनिमम चार्ज का सम्बन्ध है यह कहा जा रहा है कि अगर इसको हम हटा देते हैं तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को बड़ा नुकसान होगा। हमारी सेंट्रल गवनमेंट बहुत से मामले में सबसिडी दे रही है। क्या वह प्राविंसिस को या इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को इस मामले में सबसिडी नहीं दे सकती है ताकि काश्तकार को बिजली दी जा सके और मिनिमम चार्ज उनसे न लिया जाए? मैं चाहता हूं कि यह जो प्राविज़न है इसको आप जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश करें। फिर आप देखेंगे कि किसान पानी लेने लगेगा और पैदावार में भी बहुत वृद्धि हो जाएगी।

बाहर से जो हम अन्न मंगाते हैं उस में भी ऐसा करने से कमी आ जाएगी, वह काफी कम हो जाएगा । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो काश्तकार उन्हीं पुराने तरीकों से चर्खी से तथा और जो तरीके हैं उन्हीं से पानी लेता रहेगा । वह हमेशा पीछे रहेगा और आपका प्रोडकशन नहीं बढ़ सकेगा ।

यह कहा जाता है कि चार फरलांग या छः फरलांग के अन्दर हो तो बिजली लेने के लिए उसको नो-आबजैक्शन सर्टीफिकेट लेना होगा और तब उसको बिजली मिल सकती है वर्ना नहीं मिल सकती है । इसको आपको फौरन हटा देना चाहिये । मैं फैजाबाद जिले की बात जानता हूं । वहां पर लिफ्ट इरिगेशन और ट्यूबवेल हैं । लेकिन वहां पर लोगों को पानी ठिकाने से और समय पर काफी नहीं मिलता है । वे अपनी पैदावार बढ़ा नहीं सकते हैं ।

आप देखें कि बिजली का मामला बहुत टेढ़ा है । बिजली बराबर कटती रहती है । वक्त से बिजली और पानी उनको नहीं मिल पाता है । ट्यूबवेल वक्त से जारी नहीं हो पाते हैं । उनका पानी किसान को समय पर नहीं मिल पाता है । लिफ्ट कैनाल जो है उनकी हालत यह है कि फसल सूख रही होती है, किसान चिल्लाता रहता है उसको पानी नहीं दिया जाता है । किसान चाहता है कि वह कुएं में बिजली लगा कर पानी निकाले लेकिन उसको बिजली नहीं मिल रही है, नो-आबजैक्शन सर्टिफिकेट उसको नहीं मिल रहा है । आपने कमांड एरिया इतना बढ़ा दिया है कि उसको नो-आबजैक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है । वह पम्प नहीं लगा सकता है । इन सब चीजों को आप देखें । मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को वह यह आश्वासन दें कि उसके द्वारा मिनिमम चार्ज को हटा देने से जो कमी पैसे में पड़ेगी सैंटर से उसको उतना पैसा मिल जाएगा । उन्होंने रेट्स के बारे में कह दिया है कि बारह पैसे से ऊपर जो रेट्स हैं उनके लिए सबसिडी वह देंगे । मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी उसको कुछ करना चाहिये । अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके काफी सहूलियतें पैदा हो जाएंगी । हमारे फैजाबाद जिले में कम से कम पांच छः सौ दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं बिजली के लिए लेकिन उनको बिजली नहीं दी जा रही है । या तो नो आबजैक्शन सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से उनको बिजली नहीं मिल रही है या कुछ और कारणों से नहीं मिल रही है । मिनिमम चार्ज की वजह से भी वे लोग बिजली नहीं ले पा रहे हैं । इन सब मुश्किलात को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो एमेंडमेंट मैंने पेश किया है इसी के सिलसिले में उसको वह मंजूर कर लें । अगर मंजूर नहीं कर सकते तो कम से कम उत्तर प्रदेश के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को वह डायरेक्टिव दें और स्ट्रोंग शब्दों में दें कि वह जो ये मुश्किलात किसानों की हैं इनको दूर करें ।

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the story of electricity supply in our country is the story of hopes belied and expectations unfulfilled. The story is a story of disappointment, I am sorry to say, and the tardy progress that it has made even during the period that the Ministry has had a technocrat at its helm adds to our disappointment.

I sympathise with the hon. Minister and the ministers of power and electricity in the various States because in spite of all the assurances and expectations that were aroused very little indeed has been done and what has happened is that after the Third Five-Year Plan, in which power development did reach its zenith,

[Dr. L. M. Singhvi]

there is a virtual stagnation and stalemate. At the present juncture, therefore, the matter has acquired a fairly serious and grave urgency for this House to consider.

We clamour in different parts of the country for water and electricity. In the State from which I come this clamour is particularly insistent. You are aware, Sir, that neither water nor electricity, both of which constitute the most basic of basic amenities, have been made available in anything like a satisfactory measure. I would like particularly to emphasize, therefore, as to where we stand in terms of electricity development in different parts of our country in the world perspective because electricity is the *sine qua non* of all our progress and unless we are able to assure an integrated and planned development of electricity supply in the country, the country's progress would inevitably be arrested.

I have here some figures which are eye-openers. With only 6 per cent of the world's total population, the United States has more than 37 per cent of the world production as it was in 1961. Perhaps the percentage has increased since then. The US production of electricity actually in 1961 exceeded the combined output of six countries which come next to it, namely, Russia, United Kingdom, Japan, Germany, Canada and France. It was almost a little over three times of the country which ranks second, namely, the Soviet Union. It seems to me that by those standards we stand almost nowhere.

I have here a chart on the world production of electricity in 1961 which goes to show that of the total production of electricity in the world 37.1 per cent of the world's production was generated in the United States. Russia generated about 13 per cent; United Kingdom generated about 5.8 per cent; Japan generated about 5.3 per cent; West Germany generated about 4.9 per cent; Canada generated about 4.8 per cent; France generated about 3.1 per cent and the total estimate for a large number of other countries, including Asia, Latin America, Africa, Australia, all these countries, represents no more than 17.5 per cent. India, perhaps, represents no more than 2 per cent. If my figure is incorrect, I hope the hon. Minister would correct me. In that situation, I do not know how we are able to justify the kind of stagnation and stalemate that we have reached in this field.

16 hrs.

We talk a great deal about giving priority to food. But well after well in Rajasthan and indeed in other parts of the country looks gaping because they are unfinished, because power could not be supplied to them, because they could not be put to work, because they could not be commissioned. It seems to me that the same situation prevails in respect of industries. I know of a number of small and medium-sized industries which are today hit very hard by power famine which stalks the land almost everywhere. It seems to me that electricity ranks very low in the scheme of priorities of the Government.

We speak of idle capacity and of agricultural potential. Now, I should like to know whether the Minister has cared to make a real survey of the idle capacity which is there due largely to the non-availability of electricity in the industrial sector. I would like to know how much of the agricultural potential cannot be tapped today, cannot be put to account, because electricity is not available, because non-availability of electricity is the chief culprit. If that survey is made, if such an assessment is made, it would be found that electricity ranks very high among those factors which are lacking today in our economic development.

Electricity Board function in various States—I do not know if I should use the word 'function'. In many cases, they do not function. They are there but they have neither any development orientation nor have they

any efficiency orientation. These Electricity Boards are worse than the departmental undertakings; they are worse than the public sector under takings. I do not know how to classify them. I do not know where to place them. I would like the hon. Minister to tell us whether his Ministry has ever cared to look into the working of Electricity Boards which are, of course, in a manner of speaking autonomous organisations, which are statutory bodies but which have all the inertia, all the ineptitude, all the lack of initiative and efficiency which characterise the administration in our country today. They are sluggish; they are flabby and, what is more, they have absolutely no idea of what they are supposed to do. In the States in which Electricity Boards are recent arrivals or new-born babes, of course, the situation is worse and, unfortunately, the State from which I hail belongs to this class.

My friend, Shri Umanath, spoke of the profit motive which, he felt, corrodes the very working of Electricity Boards. I do not think tht there is anything wrong in the profit motive as such. What is wrong is this that they lack dynamism, they lack developmental orientation, they lack efficiency, they lack that approach which must make the best and most efficient service available to the consumer. Towards the consumer, they seem to take worse than the bureaucrats attitude. The bills are made out without there being any supporting evidence for such bills to be made out. The bills are pressed, the recoveries are pressed, without quite realising that those are not correctly prepared. There are thousands of cases I know, of Electricity Boards where bills are just not prepared and records are not kept. They are absolutely arbitrarily made. Somebody sits down and imagines a kind of levy or assessment that he must put on the consumer. This is what has happened in many cases. If this cannot be rectified, I think, this is like an Augean stable which will put up all the reasources but will not yield anything profitable. I think, the Government must devise something to improve matters. These Boards have failed to function in a manner that was envisaged for them.

I would like, particularly, to turn the attention of the House to the situation prevailing in Rajasthan. Only this morning, when a question was raised, the hon. Minister for Planning said that in respect of the representation made to the Prime Minister by Members from Rajasthan, it is receiving the attention of the Government, that the Government is considering the matter. Of course that is the stock reply that the Government would give to any question. The tragedy of it is that this representation was made several months ago. What is more, the substance of this representation was conveyed many months before the representation was actually made and the delegation actually met the Prime Minister. More than seven or eight months have elapsed since the situation was pointed out to the Government of India in the first instance. At any rate, three months have elapsed since we met the Prime Minister and emphasized the urgency of the situation. The stock answer still is, "We are considering the matter. It is receiving the attention of the Government." I do not know what kind of Government it is, whether it is democratic or any other Government. Any Government worth its name would not go on saying that the matter is receiving the attention of the Government. This is a kind of phrase which needs to be legislated out of existence in our country because it has become the crutches on which the Government's explanation and excuse is made day in and day out.

It is true that Rajasthan was a backward State particularly in respect of electricity. At the formation of the State of Rajasthan, only 42 localities were electrified in the whole State. Localities added during the First and the Second Plans were also 24 and 65 respectively. The Third Plan which represented the zenith of effort on the part of the Government brought about electrification of

[Dr. L. M. Singhvi]

1103 localities and then there was a kind of a full stop. Even with all this progress, in the First Plan, Rajasthan got only as much as 24 localities electrified. What a paltry kind of achievement to make. But in the Third Plan, there was a substantial measure of electrification in Rajasthan which finally brought Rajasthan to a very meagre percentage of 3·9 per cent electrification whereas the all-India average is 9·3 per cent. We are, of course, lagging far behind the more advanced States. But the disparity between the quantum of electrification achieved in Rajasthan, being 3·9 per cent, and the all-India average, which is 9·3 per cent, is very very considerable and I do not know what are the Government plans today in order to bridge this gap.

The Government is a very lofty manner declared that by the time of 2nd October, 1969, which is the birth centenary of Mahatma Gandhi, at least 1 lakh villages will be electrified and in every State, at least 20 per cent of the villages would be electrified. To achieve this target, at least 1000 localities should be declared in 1966-67 and about 1500 villages will have to be electrified in the next year. I should like to know whether the Government has any plans to fulfil this very lofty declaration or assurance given by it. It seems to me almost impossible for the Government to do so because against the requirement of nearly Rs. 650 lakhs to Rs. 750 lakhs during the first and the second year, it seems the allocation of only Rs. 250 lakhs was being thought of and this is going to be cut further. I should like to know how it is that the Government hopes to fulfil the assurances that it has given.

Mr. Deputy-Speaker: I should like, in particular, to raise this question because the question of rural water supply, the question of using wells for agriculture, the question of minor irrigation, all these hinge on the fulfilment of these promises and I should like to know whether it would be possible for the Government to do anything to achieve at least the substance of these promises or whether we should write them off as most things in this country in terms of government assurances have to be written off.

I am sorry to say that the Government proposes to make a provision for appropriating to itself the powers to see that uniformity is not preserved. What is more—and this, I think, is the most objectionable in the present Bill that is before us—Clause 24 enacts the rule of retroactivity in the legislation. In the Statement of Objects and Reasons to this Bill, no more than a word is said—It is proposed to bring into force the new provisions relating to the financial operations of the licensees retrospectively with effect from the 1st April, 1965—as if retroactivity is not looked down upon by all democratic legislatures, as if the Government did not have to give any special reasons to justify the retroactivity, if retroactivity can be justified at all under any circumstances.

I should like, Mr. Deputy-Speaker, that then the hon. Minister rises to reply, he meets some of the objections and points that I have raised and is able to reassure us at least in part. If that is not done, then, of course, the whole question of electricity supply will merge and fade into the general picture of disappointment and frustraction which stalk the land today.

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): I rise support the measure that is before us.

I find that a lot of progress has been made and every effort is made to provide pawer for agriculture. In a number of villages, at least in my State of Maharashtra, I find that power is being provided for agricultural purposes. Still I think it is very necessary that more and more power should be given for agricultural purposes because it is very difficult for a farmer

or a cultivator to draw water with the help of bullocks or with the help of diesel engines which are very costly. In that context, I may say that more and more efforts are necessary to provide cheaper electricity for agricultural purposes.

Another point that I would like to stress is about the idle period. In rainy season electricity is not required for agricultural purposes. The pumps remain idle; still the cultivators has to pay some minimum charges; he has to pay about Rs. 18 or 19 per month, whether he uses the pump or not, for three or four months. The same is the case in some cases in summer when the wells are dry; still the cultivator has to pay though electricity is not being used for these pumps. This point was raised time and again in other meetings also and I hope the hon. Minister would attend to this and see that in all the States the minimum charges from the cultivators are not recovered for idle capacity.

Another point that I would like to stress is about uniformity of rates. This point has been stressed by a number of members and I add that there should be uniformity of rates in all the States. I hope that this would be done.

Some hon. members objected to the Members of Parliament and State Legislatures being members of the State Electricity Boards. The point raised is that they should wait for 12 months, that is, for one year. I do not know the reasoning or the logic behind this waiting. Is a Member of Parliament or State Legislature, who is a politician and who has got some experience in Parliament or Legislature, less qualified? Why should he wait for one year? Is he not equally qualified as soon as he ceases to be a member and is appointed as a member of the State Electricity Board? What is the harm if he does so? I think the criticism levelled is simply for the sake of criticism and there is no basis or foundation for it. Nobody can be better qualified, nobody can be better experienced because he is not in the Parliament or State Legislature for one year. On the contrary, I feel that as soon as one ceases to be a Member of Parliament or State Legislature, if he is in a position to give his services, his services should be utilised; his experience in the Parliament or State Legislature whatever it is, should be utilised for the working of the Electricity Boards. There is no harm in that. Whether a Congress-man is to be appointed or whether a member from the Opposition is to be appointed, that is for the Government to decide. This amendment serves a better purpose and I think that it should be welcomed instead of being a target of criticism by some hon. members.

Another point that I want to make is about publication. I feel that publication is necessary. Government is thinking that with regard to projects costing about Rs. 25 lakhs, there should be no publication; with regard to projects costing less than Rs. 1 crore, there should be publication once; and with regard to projects costing more than Rs. 1 crore, the publication should be made twice. I think publication is very necessary because the public may give some valuable suggestions; the public may point out certain mistakes; they should have an opportunity to show some new methods; So it is very necessary that this publication, whether the project costs Rs. 25 lakhs or Rs. 1 crore, should be made and I am not able to follow the logic behind the amendment that there should be no publication simply because the project costs Rs. 25 lakhs and less.

Regarding the amendment to section 49, I welcome it not because the Bombay High Court decides one way or the other. but it is very necessary. But in a compact area and in the other area, the rates may differ. One has to carry electricity to a corner and in that, the cost may increase and the divergence of rates is bound to be there. Therefore, this amendment is

[Dr. L. M. Singhvi]

very necessary in order to overcome the decision given by the Bombay High Court.

With these remarks, I support the measure that is before the House.

श्री यशपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय अगर माननीय के० एल० राव साहब मसला हल करना चाहें तो यह मसला एक महिने में हल हो सकता है। हिन्दुस्तान को आज हर जगह जो भीख मांगनी पड़ रही है इसका कारण यह है कि इन में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वह करना नहीं चाहते हैं। अगर वह करना चाहें तो यह मसला हल हो सकता है। मैं कुछ सुझाव देता हूं। उस को मान लें। नीयत इनकी साफ है। नीयत में कोई शक नहीं है। लेकिन इनके करने का तरीका इतना गलत है कि उस तरीके से यह 100 साल तक भी इस मसले को हल नहीं कर सकते। गीता माता का यह हुक्म है कि विधि निषिद्ध किया हुआ कर्म कर्त्ता को मार डालता है। अगर विधि के खिलाफ आपने काम किया है तो यह मसला हल नहीं होगा। मैं आपको राय देता हूं अगर उससे एक महिने में यह मसला हल न हो तो मैं इस हाउस में मिलना बन्द कर दूंगा।

सबसे पहले सिनेमा घरों को बन्द करके यह बिजली ट्यूबवेल्स को दी जाए। सिनेमा घर बन्द किये जायें और यह जो एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इस सप्लाई को आप ट्यूबवेल्स को दें। ट्यूबवेल्स को जब तक बिजली नहीं मिलेगी, खूराक का मसला कैसे हल हो जाएगा? आपकी नीयत तो साफ है। लेकिन आपका तरीका बिलकुल गलत है। आप इस बात को जानते हैं:

The way to hell is paved with good intentions.

आपका तरीका अगर गलत न होता तो क्या 18 सालों में यह मसला हल न होता। मैं अपनी बात नहीं कहता, यू० पी० कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के बयान से मैं बताता हूं। बाबू गोविन्द सहाय जी ने यह बयान दिया है कि बिजनौर जिले के 80 प्रतिशत ट्यूबवेल इसलिए बेकार हो गए कि बिजली दूसरे कामों के लिए चली जाती है और खेती के लिए नहीं मिलती। यह मेरा नहीं कांग्रेस के एक बहुत बड़े आदमी का बयान है। तो इस बात को अगर आप हल करना चाहते हैं तो इस तरह से हल नहीं कर सकते हैं। इस बिल को मैंने देखा यह तो किसी क्लब को डिबेट में होता तो ज्यादा अच्छा था। क्या सजा दी गई है उन अफसरान के लिए जिनको कि आठ-आठ घंटे बिजली बन्द किए हुए हो गए हैं?

मैं कहीं बाहर की बात नहीं कहता हूं, जहां एम-पीज रहते हैं, वहां की बात नहीं कहता हूं, बल्कि इस हाउस की बात कहता हूं, आधा घंटा पहले मुझे हाथ धोने जाना पड़ा, 15 मिनट तक हाउस में पानी नहीं रहा, जिनके घर पानी के लिए प्यासे पड़े हैं, उस देश से यह आशा करें कि मसला हल हो जाएगा, नहीं हो सकता। जब तक निष्कर्मण्यता और भ्रष्टाचार को नहीं समझा जाएगा, पुरुषार्थ-हीनता और करप्शन को नहीं समझा जाएगा, जो बेकार बैठे हुए हैं, वे करप्ट नहीं समझे जायेंगे, तब तक यह मसला हल नही हो सकता। आज 24 घन्टे के अन्दर 6 घंटे भी काम नहीं होता। जिन्होंने अपनी आजादी की रक्षा की है, उनके यहां एवर-ओपन ट्यूबवेल्ज हैं, एवर-ओपन मार्केट है, एवर-ओपन शाप्स हैं, एवर-ओपन आफिसिज हैं, लेकिन यहां 24 घन्टे में 6 घंटे भी काम नहीं होता है। क्योंकि वे लोग जो वाटर वर्क्स के इन्चार्ज हैं, इलैक्ट्रिसिटी के इन्चार्ज हैं, जो लोग शतरंज में टाइम बरबाद कर रहे हैं, बताइये ऐसे कितने लोगों का चालान किया गया। देश में जो सबसे ज्यादा काम खराब करता है, उसको ज्यादा तनख्वाह मिलती है। आज देश की असमत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किसी के साथ कोई स्टेप लिया गया हो तो बतलाइये, किसी को सजा दी गई हो तो बतलाइये।

आप इस चीज को नोट कर लीजिये कि अगर आप देश की खेती का मसला हल करना चाहते हैं ट्यूबवेल्ज के द्वारा तो जब तक यह काम पंचायतों के हाथ में नहीं देंगे, यानी इलैक्ट्रिसिटी का काम पंचायतों के हाथ में नहीं देंगे, तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता। एक तरफ़ आप कहते हैं कि फूड का मसला हल नहीं होता है, दूसरी तरफ आप ट्यूबवेल आपरेटर को कितनी तनख्वाह देते हैं, सिर्फ 70 रुपये देते हैं। ट्यूबवेल आपरेटर ने गांव में अपनी तनख्वाह बांधी हुई है, जो उसको 50 रुपये देगा, उसके खेत में पानी जायेगा, न किसान 50 रुपये दे सकता है और न खेत में पानी जा सकता है। आपको आज देश के लिये एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। कहीं बिजली बोर्ड देता है, कहीं कम्पनियां देती हैं, वे कम्पनियां हरामखोरी कर रही हैं, मनाफाखोरी कर रही हैं, लेकिन आप उनका नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते। आप इस बात को समझ लीजिये कि यदि आप उनका नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते तो किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच सकता।

मैं आप से पूछना चाहता हूं—आप कहते हैं कि किसानों का राज्य है, लेकिन किसानों को आप बिजली 19 पैसे यूनिट पर देते हैं। जब कि बिरला साहब को 3 पैसे यूनिट पर देते हैं। जो आपका अन्नदाता है उसको 19 पैसे पर देते हैं, लेकिन जो बैठकर देश को चूसनेवाले लोग हैं उनको तीन पैसे में देते हैं। अगर इस सिस्टम को हटायेगें तो देश आगे बढ़ेगा, अगर नहीं हटायेगें तो हालत और बिगड़ती चली जायगी। अभी कल मेरे मेहमान आये हुए थे, दो-दो घंटे तक बिजली फेल रहती है, जो एम-पीज हैं वे दो घन्टे तक अन्धेरे में बैठे रहे लेकिन जिन्होंने देश की रक्षा की है, उनके यहां एक मिनट के लिये भी अन्धेरा नहीं हुआ।

हमारे यहां वेदों में लिखा हुआ है कि रविवार के दिन जो छुट्टी करता है, वह उन्नति नहीं कर सकता –

सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं, यो न तन्द्रयते चरन।

सूरज के दिन जो छुट्टी करता है, घर बैठता है, वह हरगीज आगे नहीं बढ़ सकता। यह देश छुट्टियों के नीचे दब गया है। इस देश के अन्दर निष्कर्मण्यता का जोर है, जब तक निष्कर्मण्यता नहीं हटेगी, देश नहीं बच सकता। मुझे इस समय सरदार प्रताप सिंह का स्मरण आता है। स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों कर्मवीर थे। मैं जानता हूं जिस समय वह कांगड़ा वैली में गये, वहां पर लोगों ने कहा कि हम आपको लाखों रुपये के सेव दे सकते हैं, यदि हमको 500 ट्यूबवेल दे दिये जायें। उन्होंने चीफ़ इन्जीनियर से पूछा पब्लिक के सामने कि इसमें कितना वक्त लगेगा। उसने कहा कि इसमें पांच साल लगेगें। प्रताप सिंह ने कहा कि मैं तीन महिने में तैयार देखना चाहता हूं, अगर तैयार नहीं हो सकता तो मैं इस चीफ़ इन्जीनियर को हटा कर दूसरा बुला लूंगा और वह काम तीन महिने में तैयार हो सका।

आज 50 हजार काश्तकार दरखवास्त लिये फिरते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती। मैंने यू० पी० के मिनिस्टर साहब से लिखवाया कि इनको बिजली फौरन मिलनी चाहिये लेकिन इन्जीनियर साहब बिजली स्पलाई करने के बजाय कहते हैं कि ये वजीर साहब पढ़ कर थोड़े ही आये हैं, ये मिनिस्टर साहब कानून नहीं जानते, इनको गवर्नमेंट के किसी कानून का पता नहीं है, उनको तो वोट लेने हैं, इस लिये लिख दिया, लेकिन मुझे वोट नहीं लेने हैं, मैं बिजली नहीं दे सकता। काम करने वाले काम करना नहीं चाहते, किस तरह से यह काम चलेगा। आप इस बात को नोट कर लीजिये कि जब तक आप किसानों को बोर्ड में नहीं लेते, किसान का बेटा बोर्ड का चैयरमैन हों, किसान का बेटा बोर्ड का मेम्बर हो, तब तक ये मसले हल नहीं हो सकते। अगर आप यह चाहते हों कि पूंजीपति इसके सिर पर आकर बैठ जायें, वे अफसरान जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में यह समझा था कि काम

[श्री यशपाल सिंह]

करना हमारा फर्ज नहीं है, हकूमत करना हमारा फर्ज है, हमारा काम काले आदमियों से काम लेना है, जिन्होंने यह काम किया था, वे जनतन्त्र के साथ हरगिज नहीं चल सकते।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : वे नोट नहीं ले रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह: नोट ले रहे हैं। अगर नोट नहीं लेंगे तो खता खायेंगे। यह क्या आपके लिये कम शर्म की बात है कि 22 लाख का मुल्क है डेनमार्क, वह आपके बच्चों के लिये भीख भेज रहा है। यह क्या कम शर्म की बात है कि अमरीका से जो दान आता है, उस दान की आप पब्लिक से कीमत लेते हैं, दान की कीमत वसूल करते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से किसानों के पास जाइये, खेतों को देखिये, ट्यूब-वेल्ज़ को देखिये, यह मसला एक महिने में हल हो जायगा, किसानों के लिये पानी का इन्तज़ाम कीजिये, आपको किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी।

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): The object of this Bill is to remove certain anomalies and difficulties experienced in the working of the Electricity (Supply) Act, 1948. It is proposed in this Bill to make certain changes for raising capital required for development and for tightening control over the financial operations of private licensees.

As far as the private licensees are concerned, the Tata Hydro-Power Co. in Bombay and the Electric Supply Co. of Ahmedabad were established very many years back, and they have rendered very useful and valuable services to the people of those areas. If we want to acquire them or stop the operation of these licensees, then ours being a country of law and order, we must pay adequate compensation to them or terminate the contract when the proper time arrives for that purpose. Unless that is done, we cannot take any steps to do away with them. We have to tolerate them and let them work. After all these companies have been functioning in proper way.

On page 4, in clause 11, sub-section (2) of section 49, it has been provided:

> '(d) the extension and cheapening of supplies of electricity to sparsely developed areas.'.

Many hon. Members have stated that electricity should be given to the backward areas. I entirely agree with that suggestion. At the same time, I wish to bring it to the notice of the hon. Minister that there are certain other matters also which have to be attended to. I have seen in my constituency that many villages have been given electricity. But the people are so poor that they cannot make its use except perhaps the *panchayats* which make use of it for street lights. The people who are living in huts cannot make use of this electricity.

The purpose for which electricity is supplied to the villages is agricultural. The people in the villages are too poor either to dig wells or to provide electrical motor pumps even if they have the wells. So, along with the supply of electricity we must see that electrical motor pumps are also supplied to the farmers. That is my earnest request. Merely providing electricity to villages is not enough.

Shri Bade: Also lower rates.

Shri Narendra Singh Mahida: Yes. In my State of Gujarat, the Government has very recently passed orders to the effect that electricity should be supplied at very concessional rates to agriculturists. Not only that. The surcharge realised from January onwards is also to be refunded with retrospective effect.

The type of electrical power that we have in our country should also be noted. We have at present thermal

power and hydro power. We have also atomic power which is coming up at Tarapore very soon. Now, the rates for atomic power, thermal power and hydro power differ. The cheapest power is hydro power. If we are talking about a common grid or common rate all over the country, then we shall have to have an all-Andia electricity grid system. Unless we integrate and unify all the schemes, we will not be able to give standard rates everywhere. I presume the Government is thinking in terms of unifying all the electricity boards and have a unified rate system for supplying electricity. Unless this is done, I do not think we can have uniform and equal rates for all the States.

Dr. Singhvi referred to the working of Electricity Board in his State. In my State of Gujarat, the Electricity Board has functioned very well. We had a very efficient Chairman who to my knowledge worked in that capacity without taking any remuneration. Shri H. M. Patel who was till lately the Chairman has done very useful work. I am proud of his achievements. So when Members criticise and say that MPs or MLAs when they retire are keen to go over to Electricity Boards as Chairmen or as members, let me remind them that in Gujarat we did not have any member of legislature to my information as a member of State Electricity Board.

I concede that there are certain complaints about the working of electricity boards. Very recently, the Chief Minister of Gujarat, received many complaints that electrical power is not made easily available. Electricity is demanded by villagers in large numbers for agricultural purposes. The supply is limited and all the demand cannot be fully met. The method of supplying electricity will also have to be looked into. I am quite sure the Electricity Boards will manage their affairs properly, and if supervision is necessary, the Central Government should give guidance.

16.34 hrs.

[SHRIMATI RENUKA CHAKRAVARTTY *in the Chair*].

As regards doing away with private licensees, we have some experience in my State of Gujarat. The Government there wanted to take over the private licences. But those parties went to the High Court and succeeded in obtaining a judgment that the Government has no right to abolish them without payment of compensation; or it should wait till the expiry of their term of contract. That is why even if the Electricity Boards of different States want to remove the private licensees, they cannot do so without paying heavy compensation. So this factor of taking over private licensees should be looked into and they must be paid compensation.

As far as supply of electricity to rural areas is concerned, as one hon. Member said, in urban areas 70 per cent of electricity is consumed by industries whereas the rural areas are using only 10 per cent. Modern civilisation is judged by the quantity of electricity used. If we think in terms of spreading electricity to the rural areas in India which are still backward, it is a stupendous task and for that we shall need lot of money, not only for the supply of electricity, but also for providing them with agricultural machinery that they require for tilling the land.

We must also impose very heavy punishment on illegal use of electricity. I know of some cases where people have tampered with electricity, utilised it without payment of any charges. I have recently seen that certain people have developed the art of removing the fuse at the proper time when public meetings are being addressed. So, when we have public meetings, by whichever party, these fuses should not go off.

In the villages the people must be taught about the dangers of electricity; a mere English notice of danger is not

[Shri Narendra Singh Mahida]

enough. There are leakages of electricity in the earthing wires or on the steel frame of pillar. Many children or cattle when they touch these wires or the frame receive electric shock and they perish. So, in the rural areas, wide publicity should be given about the dangers of electricity.

I have noticed in the villages of my constituency that still proper use of electricity is not made. Except for a radio or a fan working in the village, people still wait for greater use of electricity for agricultural purposes. After all, if the aim of our Government is to supply electricity to our farmers, we must utilise proper means for utilisation of electricity.

With these words I welcome this Bill and I hope the Minister and his colleague, the Agriculture Minister, will provide electricity plus the necessity of water pumps and wells to the farmers. Only if that is done, this country can rise; otherwise, we shall have to wait for many, many years in pulling up the agriculturists.

Mr. Chairman: Already we have exceeded the time limit set by the Business Advisory Committee and accepted by this House. We should have finished this Bill by about 5 O'Clock, but we are still at the first reading. I suppose the hon. Minister will take about half an hour.

Dr. K. L. Rao: 20 minutes.

Shri Sheo Narain (Bansi): We have a few words to say.

Mr. Chairman: I call upon the hon. Minister to speak now. The second reading will be taken up tomorrow. Other hon. Members who desire to speak will have to speak in the second reading.

Dr. K. L. Rao: I must express at the outset my grateful thanks to the various hon. Members for participating in this discussion on the Electricity Amendment Bill. Actually I find that the hon. Members have very rightly taken this opportunity to discuss about the problem of electricity and the electricity situation in this country, rather than confine themselves to a consideration of the limited Bill that is placed before the hon. House.

It is quite natural and correct to say that electricity is a basic factor on which the nation should be built up. There are no two opinions about it. If the USSR is today in the highest position, if it is today almost the second resourceful nation in the world, it is because it has made tremendous strides in electric power. Only 40 years back USSR was at the same level as India. Both of us produced about the same amount of power, there was very little amount of power, but in these 40 years USSR has marched very greatly ahead and today its installed capacity is 110 million KW which is second largest in the world, whereas we have got only 11 million KW, that is one-tenth of what the USSR has. That is where unfortunately our position is. Therefore, it is obvious that the position of power has to be improved in this country or to put it in another way, the *per capita* generation of power in this country today is about 75 kw hours whereas in advanced nations it is anything like 2,000 kw hours. Of course in USA and other countries it is extending even upto 5,000 or 10,000 in Sweden and Norway. We are only at 75 and therefore we realise that we should march as rapidly as possible in order to improve this position. We have two handicaps in this. Power is a very heavy capital intensive industry and requires a large amount of capital; it requires machines. Unfortunately in this country all these machines are coming from outside, causing a heavy drain on foreign exchange. The Government has set up three factories at Bhopal, Hardwar and Hyderabad and when they go into production and manufacture equipment it will be time

for us to take a big lead in power production. The other handicap is capital, resources that we can muster. The hon. Member from Jodhpur observed that we have not done well at all in electricity. I can only say that he is wrong. From 6,000 kw hours ten years ago we have multiplied our production to 36,000 kw hours in spite of great handicaps. We have made fairly good advances. But I realise the importance of electricity in the building-up of the prosperity, and I do not feel anyway satisfied, much less when we have come nowhere near the limit which we should aim at as the minimum. We should get at least 500 kw hours *per capita* from the present 75 kw today. If we can do it by at least 1980, in the next fifteen years, we would have put the nation on very good footing.

The House was very much concerned with the utilisation of power and electricity for agricultural purposes. It is quite correct because in our country 80 per cent of our population is agricultural and lives in the rural areas. in order to serve them we utilise only five per cent of our electrical energy and 95 per cent is going to the urban areas. The hon. Members were right in insisting that we should spend more of this energy for the benefit of the rural areas. Unfortunately our country is a very big one, unlike countries in Europe. In a big-sized country, it requires long and lengthy transmission lines. For instance. the Rihand power could simply have been dumped into Gorakhpur and eastern U.P. but the trouble here was the absence of transmission lines. Transmission lines take as much as the generation if generation costs Rs. 100 crores, transmission line takes equally Rs. 100 crores; that is the general rule abroad; in our country it will take much more. So, we have to have more of this generation and more of these transmission lines. Electrical energy itself is invisible but it has to pass through wires; nobody has invented to transmit electrical energy without wires. So, wires have got to be there. We have therefore got to build up large number of transmission lines and that means a lot of money. That is where we get stuck up. We are gradually building up. We are building the country into five regional grids and we are attempting now to build up an intimate grid within the region and later on to connect it with the other. In the course of the next five or ten years, we expect an all-India grid and once we have lines laid everywhere it will be easy for us to go in a big way to supply electricity for the whole areas. I may submit that I am most anxious myself about serving the rural areas, because I myself come from a village, and I know especially in the present economic situation, how much it is that the use of electricity has grown and is demanded, and how it simplifies the work and reduces the cost of agricultural pumping. The utilisation of bullocks requires nearly Rs. 90 per acre, whereas with electricity, you can do it with just Rs. 10 to Rs. 15. Agriculture requires it. That is why in any part of India, the peasant always asks for electricity, for *bijli*. Therefore, that is most important for us, and it is very essential that we should produce electricity for the people.

We have in our country 50 lakh wells, and we have electrified so far five lakh wells. We have still to electrify, therefore, 45 lakh wells, and in the coming fourth Plan, we shall electrify at least seven lakh wells. That is the main aim for the fourth Plan so far as electricity is concerned.

It is interesting to observe that the use of electricity is so much that my hon. friend from Pudukkottai, Madras state, complained that the wells there have not been electrified. This is in spite of the fact that Madras is the only State in the whole country which has got the maximum amount of rural electrification, for which funds are given on a fairly large scale. For example, this year, we have provided Rs. 6 crores for rural electrification in Madras as against Rs. 2.5 crores for

[Dr. K. L. Rao]

my hon. friend from Jodhpur, that is to say, for Rajasthan. In spite of that, the hon. Member complained that they are not having sufficient amount of money for serving the wells. It is quite true. I submit that there are a large number of wells awaiting electrification all over the country, and it is for us, therefore, to find out what are the best priority areas, and which one we should take up and which are the ones that we could do economically, that is to say, whether they are nearer the grid lines and so on. These procedures have to be adopted in the next five years and once you have the grid line, we could see which are the nearer the grid line, and where it would be much easier and economically cheaper to go in and provide electricity for these wells. Therefore, what I submit is that electrification of wells has to go on some sort of a programme for a while. After we pass through that good, grid system, it would be possible for us to take a big lead.

I am quite aware that in this country of ours, we have a great, favourable feature, namely, first-rate underground resource of water, which I think very few countries have. It is not only surface water which we have, but we have a vast ocean of excellent water underground, especially in the Gangetic basin and in Madhya Pradesh and in the coastal areas. We must have tubewells which could puncture the ground and take out the copius supply of water and bring it to surface. That is very essential. Therefore, food production in this country very greatly depends upon the utilisation of underground water and to that extent electricity has to be accelerated and has to be supplied in greater quantities and to a larger number of places.

I would submit to the House that hon. Members will have an opportunity to support this Ministry before long, when the fourth Plan will be before them. It is then for the hon. House to ask for larger funds for rural electrification. If the hon. Members maintain the same enthusiasm then, or remember this day, I only hope that they will have provided more funds for this purpose and we can serve you better and secure more electrification for rural areas and for agricultural pumping.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): May I ask one question? Will the scheme for sinking wells also be included in the scheme for electrification for tapping sub-oil water currents.

Dr. K. L. Rao: Sinking of wel's and purchase of pumps are not the concern of this Ministry. The Ministry of Food and Agriculture does give sufficient funds for sinking wells as also for the purchase of pumps. We are concerned with the supply of electricity and electric connections.

Shri Narendra Singh Mahida: The Agriculture Ministry does not deal with it but they advise the Members to go to land mortgage banks.

Dr. K. L. Rao: The policy is one of subsidy by way of assistance, whatever you may call it. The Agriculture Ministry looks after these two items. We are concerned only with the supply of power, and I can submit that so far as the power position is concerned, we have sufficient power for dealing with agriculture. There is no difficulty about power. The main trouble is, we do not have the lines. Every village costs Rs. 40,000 to Rs. 1 lakh for connections. Unfortunately copper and aluminium are in short supply and they have to be got from outside. We are engaged in a very intensive search to find out substitute materials, but till we succeed in it, so long as we depend on the conventional materials for transmission, I am afraid we have to go on limping for some time more.

While I entirely agree with hon. members in their desire to provide electricity for agriculture—pump sets, etc.—there is no occasion for that to be provided in this Bill. That is a

general policy. While I was listening to the speeches today, I was myself feeling whether we should have taken more steps to study the various aspects of the problems of wells and tubewells in various parts of the country and see to what extent the difficulties can be removed. That is a subject for close study. The ministry will be taking necessary steps to call for a conference of those States which are interested in wells and tubewells and find out what exactly the troubles are, what are the things standing in the way of implementing their projects, etc. But the function of this Bill is entirely different, *viz.*, to make some urgent changes.

The hon. member from Gorakhpur very rightly said that we should have taken a comprehensive view of the whole affair. I agree. I was myself feeling that the language itself is so funny and it was drafted by an Englishman in 1946. We can simplify it very much, but it takes time. I hope in the next session hon. members will be given a Bill which will be much more simplified and more comprehensive. But as I said yesterday, there are two reasons which make this Bill urgent. At the present moment, this Act does not allow any uniform rate. This was challenged by the Kalyan Borough Municipality of Maharashtra. They filed a suit and won it in the High Court. Similarly in Punjab and Bihar also these cases have come up. We cannot allow these cases to go through. It is meaningless. On the one hand hon. members are saying that there should be a uniform rate not only within each State but in the whole country. And quite rightly so. When the present Act does not allow the application of uniform rates, it is very necessary that we should pass a Bill nullifying it and making it possible to introduce a uniform rate. That is the urgency.

Shri Bade: Nobody objected to that provision.

Dr. K. L. Rao: My senior and respected leader in the Congress Party, Mr. Bibhuti Mishra was so angry with me that he said he would not support this Bill because it does not say anything about uniform rate for agriculture, about the rate for agriculture being less than the rate for industry and son. As I said earlier, that is a general policy and this Bill is intended to make some very urgent changes.

Another thing is, the bank rate has gone up. It has been changed in February, 1965. It is good that the private licensees have not taken advantage of this and raised the rates. Under the Act they could have done it. Therefore, what we have now sought is to say that on investments made so far—in 1965—we shall allow a bank rate of 7 per cent and for investments later on it shall be 2 per cent. Otherwise, what will happen is this. Let us say that the net assets, to give an approximate figure, of private licensees in the country is Rs. 120 crores. The amount of clear profit they can get will be calculated on the basis of standard rate. According to that, 8 per cent of Rs. 120 crores will be nearly Rs. nine and a half crores, whereas if it is 7 per cent it will only be in the order of Rs. eight and a half crores. There is a difference of Rs. 1 crore. That means they have to gain it by increasing the rates. It is not correct to do so because they have acquired the assets in those days when the bank rate was 5 per cent or even 3 per cent. Therefore, while I greatly respect Shri Dandekar's principles of equity and proper perspective in dealing with this, I am afraid, when you come to private licensees in the matter of electricity I should say we are perfectly correct in introducing this amendment. We have thought out the matter very carefully to see whether there was any moral turpitude involved in this matter. I do not find any such thing at all. What we have said is that all those assets up to 1965 will be charged at 7 per cent and any investment beyond that will be charged at the new rate. The new investment will be a small amount. I do not think anybody is going to invest hereafter in a big way. As I told you,

[Dr. K. L. Rao]

nobody except the three or four big undertakings is going to invest large amounts in this, because it is the policy of Government that private licensees shall be taken over as early as possible. Of course, I know some of the big private undertakings have been doing very good work. Those people who are having large installed capacity like the Tatas and so on are doing very good work. But there are a lot of small uneconomical units. The other day I had been to Silchar and I was surprised to find that Silchar was under a private licensee. The people there told be that the electric lights there were burning bright only that day because I had gone there, and on other days they were usually dim. I do not know how far it is true, but that is what they told me. Therefore, what I submit is, these private undertakings—not all, but some of the bad ones at least—are to be acquired as early as possible. It is our policy to do so. We want to be fair to them. Simply because the bank rate has risen, immediately we should not increase the electricity rates. There is no meaning in that. That is why this matter is urgent. It is these two urgent factors that have made us come to this hon. House for passing this Bill. That is the limited scope of this Bill.

Having got this opportunity to amend the Act, we have introduced a few other changes. I want to touch upon only one or two other amendments. Most of the hon. Members were talking about membership. I was surprised to find references being made to elections and so on. I may say, I am not accustomed to this kind of thing. In fact, it never struck me, that this provision has such a deep meaning as that. All that it provides is this. It is not Members of Parliament or members of State legislatures alone who are referred to here. Here it says: "Member of Parliament, State legislature or any local authority". That is to say, at the moment, even a panchayat Board member of a village cannot become a member of the Electricity Board. That means a very large number of Indian personnel are disqualified. Though there is corruption and all that, I cannot understand how corruption can be associated with hon. Members of legislatures. I think we should say 'nonsense' to that kind of thing. I accept Shri Yashpal Singh's definition that an idler is corrupt. I quite agree, but I would not say that hon. Members of this House, legislatures or panchayats are corrupt or anything like that. Most of the members on Electricity Boards are honorary. Only three members are permanent members, full-time officers, who are electrical engineers who have got administrative experience or other very specific qualifications. Others are all honorary members, who get a little amount of money. I do not think we should take such great objection to this provision. I do not think there is really much in that. I am really sorry, that the hon. Members, especially from the opposition, have referred to the elections and all that. As I said, it never crossed my mind. Having dealt with this subject so many months, I never thought that the question of election will be brought into this.

17 hrs.

Then, every hon. Member was talking about publication. I think there is a lot of confusion about this, especially about the limit of Rs. 25 lakhs. Shri Warrior, who has made a speech and is going away to Cochin—he has written to me a slip that he will not be here—has stated that there is something fishy about this. I want to submit very clearly that the publication has nothing to do with the tenders. Actually, I am feeling myself that probably in the next Amending Bill I should omit this provision about publication. For example, we are sanctioning Rs. 1,000 crores worth of irrigation projects. We do not publish them. Some other hon. Members referred to corruption and something

fishy in this connection. In the case of an irrigation project, if it costs Rs. 2 crores or less, it need not come to the Centre; the State can sanction it. But, in the case of electricity, every scheme has to come to the Centre, has to pass through very rigid scrutiny by the Central Water and Power Commission, Technical Advisory Committee and so on. Therefore, there is greater rigidity, greater control of electricity schemes than in the case of irrigation projects. Still, we do not publish those irrigation projects. We are publishing the electricity schemes merely to acquaint the people with the scheme. It was enunciated in the olden days when the generation of electricity was very little and we had to popularise it.

Shri Narendra Singh Mahida: Then, what is your objection to publishing it?

Dr. K. L. Rao: Then, as hon. Members know, Rs. 25 lakhs means nothing today. It is a very small amount. In the olden days, 130 years ago, Sir Henry Cotton completed the Godavari system for Rs. 14 lakhs. Today it will cost anything like Rs. 200 crores. Therefore, Rs. 25 lakhs is a small amount today. That is why in the case of an irrigation project we have got a limit of Rs. 15 lakhs for minor irrigation Rs. five crore for medium irrigation and more than Rs. five crores for major irrigation. This is just a sort of artificial limit. There is no sanctity about this Rs. 25 lakhs. If the hon. Members want to fix it at Rs. 20 lakhs, we can do it. We want to put a higer limit because otherwise there will be a large number of such schemes. There is no point in publishing all of them. It will mean waste of money, because we have to publish them in the paper Also, it causes delay.

Shri N. Dandeker: Then why publish projects costing Rs. 1 crore and more? What is the point?

Dr. K. L. Rao: I am coming to that. Projects costing less than Rs. 25 lakhs will be large in number. Projects costing more than Rs. 1 crore will be few.

Shri N. Dandeker: Why publish them at all?

Dr. K. L. Rao: A majority of the projects belong to the category of medium and minor. Projects costing Rs. 25 lakhs or less will be a large number. There is no meaning in publishing them once or twice. It causes delay of months.

Shri Bade: Then why do you not take away the publication entirely?

Dr. K. L. Rao: I will be very happy to do it. We have to do it gradually, very carefully. Hon. Members will otherwise say that we are doing something very radical. So, as I said, the next amending Bill will do way with this clause. There is no particular sanctity for this limit of Rs. 25 lakhs or Rs. 1 crore. We have simply said that for projects costing up to Rs. 25 lakhs we will not publish, for schemes between Rs. 25 lakhs and Rs. 1 crore we will publish once, and in the case of schemes costing more than Rs. 1 crore twice at the draft stage and in the final form. There is nothing to read in between the lines. The object of this publication is merely to familiarise the people with the project. This was conceived at a time when generation of electricity was very little, when it had great glamour and people did not know what electricity was. There are one or two other points which I want to deal with.

Mr. Chairman: Would he like to continue his speech tomorrow?

Dr. K. L. Rao: No, I would like to finish today. I once again thank hon. Members for the very large amount of comments that they have given. There were useful suggestions in them and we will make a particular study of these. As I submitted, though it

[Dr. K. L. Rao]

may not concern the Bill, there are a lot of useful suggestions made in respect of the electricity situation in the country and they will receive very great attention from the Ministry of Irrigation and Power.

Mr. Chairman: We will now take up the half-an-hour discussion.

17.06 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION *RE*: GANDAK PROJECT

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैडम चेयरमैन, मैंने स्टार्ड क्वेश्चन 1653 ता० 12-5-66 को रखा था । प्रश्न मेरा यह था कि गण्डक योजना के कार्यान्वयन में रुपये-पैसे की कमी के कारण से देरी हो रही है, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है । उसके बाद फखरुद्दीन साहब, जो यहां बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका जवाब मिला कि बिहार गवर्नमेंट ने 1966-67 में 9.18 करोड़ रुपया रखा है, केन्द्र सरकार ने इसके लिये तीन करोड़ रुपया दिया है और आगे इसके लिये यदि बिहार गवर्नमेंट अपने बजट में रुपया रखेगी तो काम होगा और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी इस में जो अनुदान होगा, इसके लिये खर्च करेगी ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह योजना—इसका बहुत पहले 20–22 करोड़ रुपये का अन्दाज़ लगा था, उसके बाद इसका अन्दाज़ा 36 करोड़ रुपये हुआ, 36 करोड़ के बाद 56 करोड़ रुपये हुआ और अब 56 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 124 करोड़ रुपये इसका तखमीना हो गया है । अब तक मैं समझता हूं कि इसमें कुल लगभग 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है । इस समय जो खर्च की रफ़्तार है, फखरुद्दीन साहब ने जो जवाब दिया है, यदि उसका हिसाब लगाया जाय तो इस डिवैल्यूएशन के बाद जो मंहगाई हो गई है, उसको देखते हुए स्वाभाविक है कि इसका खर्च 150 करोड़ रुपये या इससे भी ज्यादा हो जाय । यह योजना सन् 1960 में मंजूर हुई थी और अब 1966 हो गया है, इन सात वर्षों में हम ने 20 करोड़ रुपया खर्च किया है । ऐसी स्थिति में, मैडम चेयरमैन, अन्दाजा लगा लीजिये कि जब कि इस योजना का तखमीना बढ़ता जा रहा है, कब तक यह पूरी हो सकेगी ।

हमारे यहां कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी पैसा लगाया जाय और जल्दी से जल्दी उसका रिटर्न मिले । रिटर्न जो हमारे यहां जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि हिन्दुस्तान की जितनी भी योजनायें हैं उनके मुकाबले में, हिन्दुस्तान के जितने भी विज्ञान-वेत्ता और बड़े बड़े इंजीनियर हैं और खुद हमारे डा० के० एल० राव साहब, जब वह खुद इंजीनियर थे, उन्होंने कहा था कि इससे अच्छी कोई योजना नहीं है । लेकिन जब वह मिनिस्टर हो गये तो न मालूम क्यों सुस्त हो गये, इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं । यही नहीं हमारे मिनिस्टर श्री फखरुद्दीन साहब, जो जन्मजात कांग्रेसी हैं, जनसेवक हैं, इनके आने पर भी इस योजना का भाग्य ऐसा लगता है कि जो इस पर खर्च होता है, उसको देखते हुए 15-20 वर्षों से पहले हल नहीं हो पायेगी ।

इधर इसमें एक बात हुई है । राव साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि रुपये-पैसे की बड़ी दिक्कत है, इसलिये इसका इन्तजाम सोचना होगा, सरकार इसके लिये सोचेगी । इस पर हम लोग जो गण्डक-कमांडेड एरिया के लोग हैं, हम लोगों ने प्लानिंग मिनिस्टर साहब से मुलाकात की । उन बेचारों ने हमारे साथ बड़ी भलमनसाहत दिखलाई, उन्होंने फौरन दो आदमियों को इस काम के लिये लगा दिया—एक ठाकुर साहब और एक नाग साहब । ये दोनों सज्जन वहां गये, जहां पर यह योजना बन रही है, इन लोगों ने वहां जाकर देखा, हम लोग भी जो उस क्षेत्र के एम० पीज़ हैं, जैसे द्वारका नाथ तिवारी, कमल नाथ तिवारी, इन से जाकर मिले ।